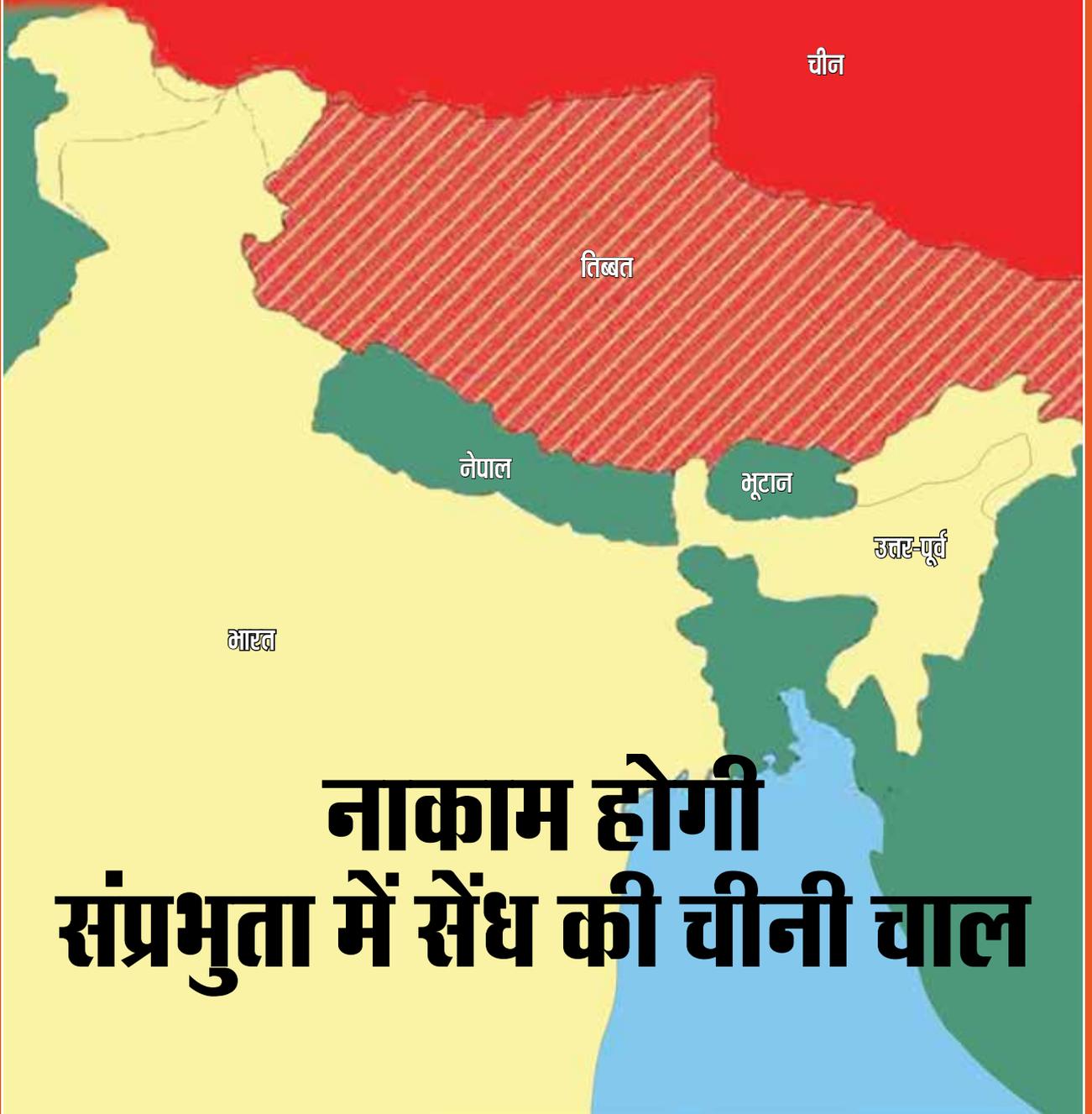




राष्ट्रीय

ऊर्जा शक्ति

वर्ष 46 ■ अंक 01 ■ अप्रैल 2024 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40



चीन

तिब्बत

नेपाल

भूटान

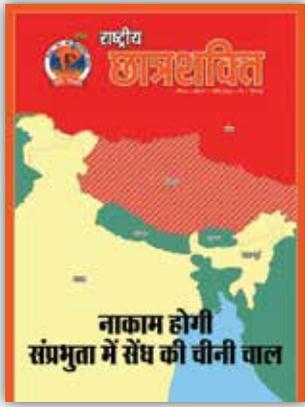
उत्तर-पूर्व

भारत

नाकाम होगी संप्रभुता में सेंध की चीनी चाल

संदेशखाली पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अभावपि का देशव्यापी प्रदर्शन





राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 46, अंक 01
अप्रैल 2024

संपादक

आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :

राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

✉ rashtriyachhatrashakti@gmail.com

📘 www.facebook.com/Rchhatrashakti

🐦 www.twitter.com/Rchhatrashakti

📷 www.instagram.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग के., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। संपादक *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

05

‘भूमि हड़पो-नाम बदलो’

सीमा पर चीन की धूर्त एवं उकसावे वाली हरकतों को भारतीय सुरक्षा बल लगातार सहन करते आ रहे हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य एवं कूटनीतिक स्तर पर जारी वार्ताओं में चीनी पक्ष शांति, समझौता और...



संपादकीय	04
An answer to China's Claim on Arunachal and Ladakh	09
पूर्ववर्ती सरकारों ने की राष्ट्रीय हितों के साथ अनदेखी !	12
आरजीपीवी में हुए भ्रष्टाचार पर अभाविप का आंदोलन जारी, मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग	13
लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून	14
डा. बी. आर. आंबेडकर : महानता मिथक न बने	16
महज घटना नहीं, अपितु मानसिकता है संदेशखाली	18
अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग	19
अभाविप के राज्य स्तरीय सम्मेलन में आसू और एनएसयूआई ने फैलाई अराजकता	20
अभाविप ने देश भर में मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस	22
अमृत महोत्सव समारोह में हुआ कार्यकर्ताओं का सम्मान	23
वीर सावरकर ने अपने प्रखर दैदीप्य से जलती लौ को बना दिया मशाल	24
सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में उभरी अभाविप, मत प्रतिशत 12 प्रतिशत बढ़ा	26
राष्ट्रीय कार्यशाला में नवाचार, उद्यमिता और स्वरोजगार पर मंथन	27
चार दिवसीय 33 वां राज्यस्तरीय सम्मेलन नवी मुंबई में संपन्न	28
भारतवासियों के डीएनए में है सेवा भाव : एस. बालकृष्ण	30
राष्ट्रीय बैठक में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर	32
राष्ट्ररंग सहित कई आयोजनों में छात्र-छात्राओं ने दिखाई सृजनात्मक क्षमता	34
NATIONWIDE PROTESTS AGAINST LEFTIST VIOLENCE	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी ने एक नए राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया है। नौ बार प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे को टालने के बाद जब उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने जमानत की प्रार्थना करने के स्थान पर गिरफ्तारी को ही चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को इस टिप्पणी के साथ निरस्त किया कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसकी जांच आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकती। इस निर्णय के विरुद्ध केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने इस पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। न्यायालयों में इस वाद का अंतिम परिणाम क्या आएगा, यह तो समय ही बताएगा, किन्तु देश से भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकने की घोषणा के साथ सत्ता में आए केजरीवाल और उनके साथियों पर प्रथम दृष्टया मामला बनने की सूचना भी जनमानस को विचलित करने के लिए काफी है। यह आपातकाल के दौरान उपजी राजनेताओं की पीढ़ी के भ्रष्टाचार में आकंट डूब जाने की घटना की पुनरावृत्ति है, जिसका साक्षी पूरा देश है।

इस बीच यह अन्तर अवश्य आया है कि तब उच्च न्यायालय के निर्णय को नकार कर आपातकाल लागू करने का निर्णय किया गया, जबकि अब संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया को ही चुनौती दी जा रही है। तब एक सत्तापक्ष था और दूसरा प्रतिपक्ष, किन्तु अब दोनों ही पक्ष सत्ता में हैं। एक पक्ष केन्द्र की सत्ता में है तो दूसरा पक्ष विभिन्न राज्यों में सरकार चला रहा है। केन्द्र के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा संचालित राज्य सरकारें रणनीतिक गठबंधन में हैं और संसद द्वारा पारित विधानों को भी अपने राज्य में लागू करने को तैयार नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अराजनीतिक मुद्दे भी इस राजनीति की भेंट चढ़ गए हैं।

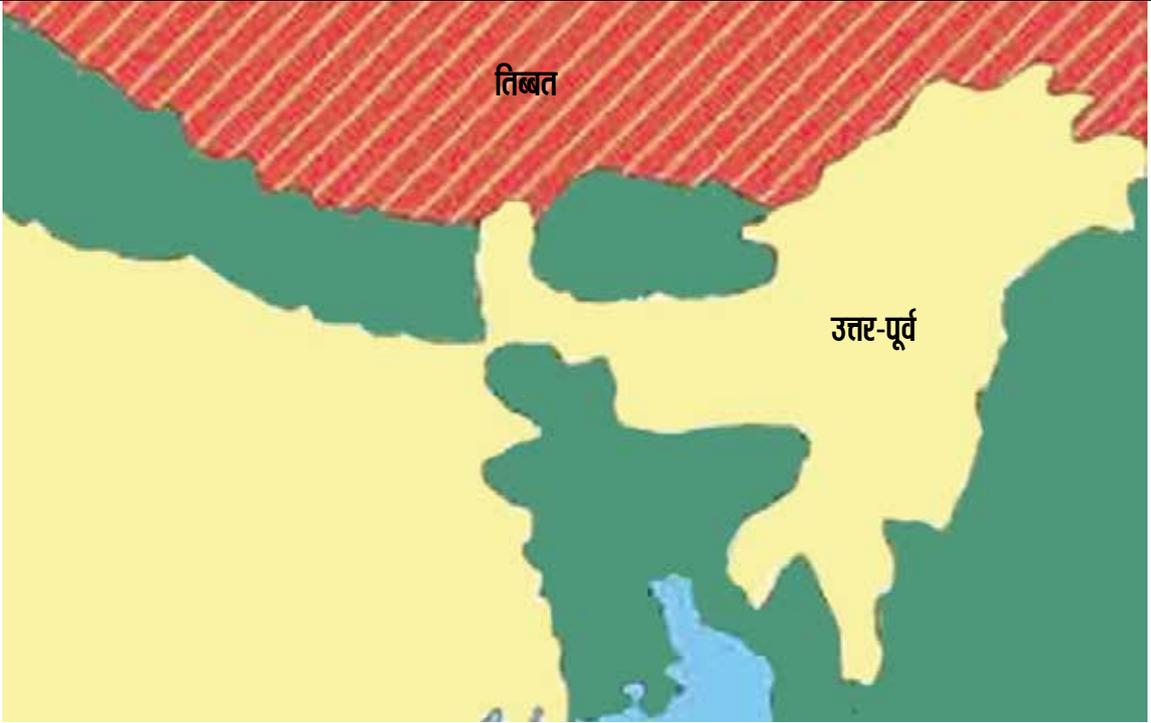
हठधर्मिता की यह राजनीति संघ-राज्य संबंधों में भी खटास उत्पन्न कर रही है। वैचारिक विरोध का रंजित में बदल जाना और इसके चलते मूल्यों में गिरावट के नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। केन्द्रीय सत्ता को चुनौती देने के जुनून में उन समूहों का भी समर्थन जुटाया जा रहा है, जो भारतीय संविधान को नकारते हैं तथा हिंसा को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के समर्थक हैं। इस समर्थन के प्रतिदान के रूप में उनकी संविधान-विरोधी गतिविधियों का संरक्षण और बचाव करना मजबूरी है।

विडंबना यह है कि राजनीति के इस विकृत रूप पर जहां से सवाल उठने चाहिए थे, वहां सन्नाटा पसरा है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे इस परिस्थिति में आगे आना और देश का बौद्धिक नेतृत्व करना चाहिए वह चुप है। विश्वविद्यालयों में जहां राजनीतिक दलों द्वारा परोसे गए आश्वासनों, वादों और प्रस्तावित नीतियों का तथ्यों और तर्कों के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए था, वहां अधिकांश ऐसे विषयों पर शोध हो रहे हैं, जिनका न कोई नीतिगत मूल्य है, न ही उपयोगिता। अधिकांश बुद्धिजीवी लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद राष्ट्रीय विमर्श को धार देने के स्थान पर अपनी रुचि के अनुसार इस या उस राजनीतिक बाड़े में अपनी जगह बना चुके हैं अथवा बदलती व्यवस्था का पूर्वानुमान कर राजनेताओं की तरह ही नए अवसरों की तलाश में हैं।

इस अंधेरे के बीच शिक्षा जगत में अभावपि एक दीप स्तंभ की भांति अपने मूल्यों पर टिकी हुई है, सक्रिय है, निरंतर वर्धमान है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को संकल्पित छात्रशक्ति तैयार करने का यह अभियान और अधिक गति से चले, यह आज की आवश्यकता है और चुनौती भी। नवसंवत्सर में हमारा यह संकल्प और अधिक दृढ़ और बलवती हो, इस शुभकामना के साथ...

आपका
संपादक

विश्वविद्यालयों में जहां राजनीतिक दलों द्वारा परोसे गए आश्वासनों, वादों और प्रस्तावित नीतियों का तथ्यों और तर्कों के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए था, वहां अधिकांश ऐसे विषयों पर शोध हो रहे हैं, जिनका न कोई नीतिगत मूल्य है, न ही उपयोगिता।



‘भूमि हड़पो-नाम बदलो’

सीमा पर चीन की धूर्त एवं उकसावे वाली हरकतों को भारतीय सुरक्षा बल लगातार सहन करते आ रहे हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य एवं कूटनीतिक स्तर पर जारी वार्ताओं में चीनी पक्ष शांति, समझौता और विकास की बड़ी-बड़ी बातें तो करता आ रहा है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चीन वास्तव में शांति चाहता है।

■ संजय दीक्षित

“अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूँ तो क्या वह घर मेरा हो जाएगा?” यह महज एक टिप्पणी नहीं है। बल्कि, यह भारत की सम्प्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रहित-पूर्ण विदेश नीति को सार्वजनिक करने वाला वह कठोर उत्तर है, जिसने चीन की ‘भूमि हड़पो-विस्तार करो’ नीति को एक बार फिर देश की जनता के सामने उजागर किया है। भारत की यह टिप्पणी चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नए स्थानों पर दावा करते हुए उनका नाम चीनी नाम पर रखने का खुलासा होने के बाद आई है।

चीन की सरकारी मीडिया के माध्यम से गत 31 अप्रैल को चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के कई नए स्थानों को अपना भू-क्षेत्र बताया और उनके नाम बदलकर चीनी भाषा में करने की सार्वजनिक घोषणा की थी। चीन के कथित दावों की लंबी श्रृंखला में जुड़े इस नए दावे को भारत ने कठोर शब्दों में रद्द कर दिया। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न भू-भाग है। कल्पना की दुनिया में भारत के भू-भाग का नाम बदलने से वास्तविक सच्चाई में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो जाता है।



चीन की धूर्ततापूर्ण नामकरण नीति

दशकों पहले 1962 में हड़पे हुए भारतीय भू-भाग यानी तिब्बत में चीन ने कई भारतीय स्थानों के नाम बदल दिए हैं। तिब्बत क्षेत्र में वास्तविक भारतीय नाम बदल कर चीनी नाम रखने का कारण बहुत स्पष्ट है। वैश्विक स्तर पर चीन किसी भी तरह कब्जाए हुए भारतीय भू-क्षेत्र को अपना भू-क्षेत्र सिद्ध करने करने की कोशिश कर रहा है। धूर्त नामकरण नीति का प्रयोग अब अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन कथित रूप से अपना जैंगनान नामक प्रान्त बताता है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2017 में प्रदेश के छह स्थानों के बदले हुए नामों की पहली सूची जारी की थी। इसके बाद 2021 में 15 स्थानों और फिर 2023 में 11 स्थानों के नाम बदल कर चीनी भाषा में करते हुए उन स्थानों को अपना भू-क्षेत्र बताया गया। इसी कड़ी में गत 31 मार्च को चीनी मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदलने की आधिकारिक घोषणा की, जिसका भारत ने कठोर भाषा में खंडन किया। अगस्त 2023 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई-चिन तथा कई अन्य क्षेत्रों पर दावा करते हुए चीन ने एक नया नक्शा भी जारी किया था, जिसे वह चीन का मानक नक्शा कहता है। चीन अपनी धूर्त नामकरण नीति से अरुणाचल प्रदेश को केंद्र में रखने की कोशिश लगातार कर रहा है।

अरुणाचल के विकास से तिलमिलाया चीन

उत्तर-पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जो चीन के साथ ग्यारह सौ किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। सामरिक, रणनीतिक एवं सुरक्षा दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों के समुचित विकास पर स्वतंत्रता के बाद से समग्र रूप से ध्यान नहीं दिया गया। जैसे-तैसे काम चलाऊ नीतियों के कारण उत्तर-पूर्वी राज्यों में बनी नकारात्मक स्थितियों में आमूलचूल बदलाव की प्रक्रिया 2014 के बाद प्रारम्भ हुई। इसके बाद उत्तर-पूर्व में बिजली, पानी, सड़क, पुल, सैन्य संरचनाओं के साथ ही अन्य आवश्यक अधोसंरचना का विकास तेजी से हुआ। विकास की इस प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण

इस प्रदेश पर चीन की गिद्ध दृष्टि दशकों से लगी हुई है।

चीन की धूर्त नीति को समझते हुए पिछले एक दशक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में सड़क, सुरंग, पुल, एयरबेस और अत्याधुनिक निगरानी तंत्र की स्थापना की दिशा में बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया गया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक पुल, सुरंग, एयरबेस के निर्माण और विकास की नई योजनाओं से प्रदेश में आए बदलाव को चीन भी महसूस कर रहा है। सामरिक दृष्टि से कई स्थानों पर ऐसे पुलों का निर्माण भी किया गया है, जहां से अति भारी सैन्य वाहन भी चीन सीमा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हाल ही में डोनी पोलो हवाईअड्डा और सेला सुरंग भी राष्ट्र को समर्पित कर दी गई, जोकि विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में 'नए भारत की-नई पहचान' बनकर सामने आई है।

प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट एक रोपवे परियोजना की निर्माण प्रक्रिया भी आरम्भ हो चुकी है। लगभग 522 करोड़ रुपए लागत वाली 5.2 किलोमीटर लंबी यह रोपवे परियोजना तवांग मठ से पीटी त्सो लेक और एल माधुरी लेक को जोड़ेगी। रोपवे परियोजना को आगामी तीन वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में तवांग एक बड़ा संवेदनशील केंद्र है। यही कारण है कि इस क्षेत्र से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क परियोजनाओं के साथ ही अन्य अधोसंरचना सम्बन्धी योजनाओं पर तेजी से हो रहे कार्यों से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है।

सेला सुरंग : 'नए भारत की नई पहचान'





अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले स्थित तवांग से असम स्थित तेजपुर को जोड़ने वाली सड़क पर तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सेला सुरंग सामरिक एवं रणनीतिक रूप से एक अति-महत्वपूर्ण अधोसंरचना है। यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में तैयार होकर सामने आई है। 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह सुरंग बालीपारा-चारिद्वार-तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग को जटिल मौसम में भी जोड़े रखेगी। इसका सर्वाधिक लाभ सशस्त्र बलों को मिलेगा क्योंकि बर्फबारी और भारी वर्षा से होने वाले भूस्खलन के कारण बालीपारा-चारीद्वार-तवांग मार्ग हर वर्ष लंबे समय तक बंद रहता है। फरवरी 2019 में सुरंग की आधारशिला रखने के बाद इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2019 में प्रारम्भ हुआ था। कठिन भू-क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों को पार करते हुए सात किलोमीटर लंबी यह सुरंग केवल पांच वर्षों में बनकर तैयार हो चुकी है। सुरंग सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी अपना योगदान करेगी। साथ ही सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने किया है।

उत्तर-पूर्व में आए बदलाव से सकते में चीन

स्वतंत्रता के बाद दशकों तक केंद्र एवं राज्य की तत्कालीन सरकारों ने सुरक्षा हितों, आर्थिक विकास एवं सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों के समाधान के लिए वास्तविक जमीनी प्रयास नहीं किए। परिणाम उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में विद्रोह, उग्रवाद, अलगाववाद एवं सामाजिक-आर्थिक असंतोष के रूप में सामने आया। उत्तर-पूर्वी राज्यों की विकास प्रक्रिया में हुई अनदेखी का लाभ चीन ने उठाया और अपरोक्ष रूप से उन तत्वों को पोषित करने में लग गया, जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। भारत विरोधी अलगाववादी एवं उग्रवादी संगठनों सहित हथियार-मादक पदार्थों के तस्करों के साथ चीन की संलिप्तता के कारण दशकों तक उत्तर-पूर्व को आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनसे सुरक्षा बल अभी भी निपट रहे हैं।

उत्तर-पूर्व के सात राज्यों में बदलाव की समग्र, सुविचारित एवं समेकित प्रक्रिया 2014 के बाद आरम्भ

हुई। गत दस वर्षों के दौरान सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व में विकास से जुड़ी योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। उत्तर- पूर्वी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद 2022 में मणिपुर में माल गाड़ी पहुंची तो 2023 में मेघालय की जनता ने बिजली के इंजन वाली रेलगाड़ी को पहली बार देखा। 2014 में उत्तर-पूर्व राज्यों से संचालित होने वाले हवाई अड्डों की संख्या 9 थी, जो अब बढ़कर 17 हो चुकी है। सड़कों का निर्माण जिस तरह से हुआ है, उसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। बोगीबिल पुल बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी ही कम नहीं हुई है, बल्कि लोगों को अनेक समस्याओं से मुक्ति मिली है। इसी तरह भूपेन हजारिका सेतु के निर्माण से भारतीय सेना को रणनीतिक लाभ मिलने के साथ-साथ चीन सीमा से लगे दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच आसान हुई है।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सहित अन्य सभी क्षेत्रों से जुड़ी विकास योजनाओं के अलावा सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन से उत्तर-पूर्वी राज्यों में हुए बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में उत्तर-पूर्व एक बड़े सहभागी की भूमिका में आ गया है। उत्तर-पूर्व में आए बदलाव की कल्पना चीन ने नहीं की थी। भारतीय भू-भाग में हो रहे बदलाव से चीन में पैदा हुई निराशा उसके बयानों से समझी जा सकती है।

कठोर सुरक्षा तंत्र से टूट रहा है चीनी नेटवर्क

उत्तर-पूर्व के राज्यों में दशकों से अलगाववाद एवं उग्रवाद को चीन अपरोक्ष रूप से पोषित करता आ रहा है। इसमें हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े तंत्र की भी अपनी भूमिका रही है। लेकिन भारत के कठोर सुरक्षा तंत्र ने पड़ोसी देशों से लेकर उत्तर-पूर्व में फैले चीनी तंत्र को बड़ा झटका दिया है। गत दस वर्षों के दौरान कठोर सुरक्षा प्रबंधों के कारण उत्तर-पूर्व के राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून का दायरा 75 प्रतिशत कम हुआ है और हिंसक उग्रवादी घटनाओं में लगभग 78 प्रतिशत की कमी आई है।

प्रगति के लिए शांति के मंत्र पर काम कर रहे सुरक्षा



तंत्र के दबाव एवं विकासपरक नीतियों का परिणाम त्रिपुरा शांति समझौता, बोडो शांति समझौता, ब्रू पुनर्वास समझौता, कार्बी आंगलोग समझौता, असम-मेघालय सीमा समझौता, आदिवासी असम शांति समझौते सहित 11 शांति समझौतों के रूप में देखा जा सकता है। असम और मेघालय के बीच गत पांच दशक से जारी सीमा विवाद समाप्त हो चुका है। शांति के तमाम प्रयासों से अलगाववादी एवं उग्रवादी संगठनों से जुड़े तत्वों में नया विश्वास पैदा हुआ। लगभग दस हजार से अधिक लोग हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। दशकों से स्थानीय स्तर पर जो विवाद हिंसा का कारण बने हुए थे, उनका समाधान इतनी आसानी से होगा, इसकी कल्पना चीन के उस तंत्र ने नहीं की थी, जो उत्तर-पूर्व में भारत विरोधी तत्वों को हवा देने में लिप्त था।

कठोर सुरक्षा प्रबंधों ने हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त उस तंत्र की कमर भी तोड़ दी है, जिसे पोषित करके चीन अपने हितों को साधने में लगा हुआ था। तस्करी का यह पूरा तंत्र चीन-म्यांमार के सीमा क्षेत्र में लम्बे समय से सक्रिय था। लेकिन इस पूरे तंत्र को जिस तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है, वह भी चीन के लिए सदमे का रूप ले चुका है।

कठोर सुरक्षा प्रबंधों ने हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त उस तंत्र की भी कमर तोड़ दी है, जिसे पोषित करके चीन अपने हितों को साधने में लगा हुआ था। तस्करी का यह पूरा तंत्र चीन-म्यांमार और बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों से सक्रिय था। इस पूरे नेटवर्क को जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, वह भी चीन के लिए सदमे का बड़ा कारण है।

लगातार उकसा रहा है चीन

पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कई बार अरुणाचल प्रदेश के अपने प्रस्तावित दौरे को रद्द कर दिया था। यह स्थिति तब पैदा हुई, जब भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की सूचना सार्वजनिक हुई और चीन ने मुखर विरोध किया। इसी रणनीति को चीन

ने उस समय भी अपनाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश दौरे पर गए। लेकिन चीन के कुतर्कों को भारत ने अनदेखा कर दिया और प्रधानमंत्री के दौरे को भारतीय भू-भाग का आधिकारिक दौरा बताया।

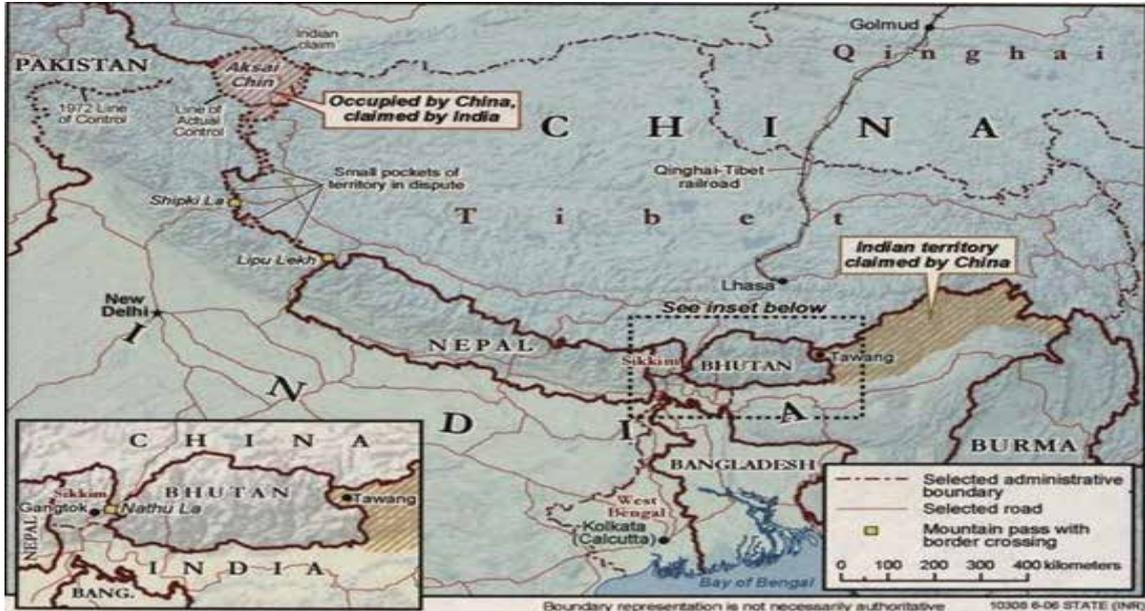
2017 के बाद से चीन लगातार भारत को उकसा रहा है। चीन यह कोशिश कर रहा है कि भारत आवेश में कोई ऐसा कदम उठाने का प्रयास करे, जिसका लाभ उठाकर वह अपने धूर्त हितों को पूरा कर सके। उकसावे की इसी रणनीति का रक्तंजित परिणाम जून 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना के रूप में पूरे विश्व ने देखा। गलवान में हुए सैन्य संघर्ष में भारत के बीस जवान शहीद हुए, लेकिन चीन की सेना के कितने जवान मारे गए, कितने घायल हुए और कितने नदी में बह गए? उनकी संख्या बताने की हिम्मत चीन नहीं जुटा सका है। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से क्षेत्र में भी चीनी सेना ने संघर्ष की स्थिति पैदा की। तवांग के पास 15 हजार फीट की ऊंचाई पर हुए इस संघर्ष में कई सैनिक घायल हुए, जिनमें चीनी सैनिकों की संख्या अधिक थी।

कहना गलत नहीं होगा कि अपने धूर्त हितों को पूरा करने के लिए चीन अपनी सेना का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्र में दबाव बनाने के लिए करता आ रहा है। चीन के दबाव को दरकिनार करके भारतीय सीमा क्षेत्र में हो रहे समग्र विकास के साथ ही सैन्य एवं अन्य अधोसंरचना का तेजी से निर्माण, नए सैन्य उपकरण, नई युद्धक तकनीकियों का विकास एवं नई पीढ़ी के हथियारों के साथ ही रक्षा क्षेत्र में बढ़ती हुई भारत की शक्ति भी एक बड़ा कारण है, जिसे चीन असहज होकर स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

सीमा पर चीन की धूर्त एवं उकसावे वाली हरकतों को भारतीय सुरक्षा बल लगातार सहन करते आ रहे हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य एवं कूटनीतिक स्तर पर जारी वार्ताओं में चीनी पक्ष शांति, समझौता और विकास की बड़ी-बड़ी बातें तो करता आ रहा है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चीन वास्तव में शांति चाहता है। देखना यह होगा कि आगामी समय में क्या स्थितियां बनती हैं? परन्तु सीमान्त क्षेत्रों में चीन की धूर्त और मक्कारी पूर्ण चालबाजियों से भारत कठोरता के साथ निपट रहा है और चीन का असली दर्द भी यही है। ■

AN ANSWER TO CHINA'S CLAIM ON ARUNACHAL AND LADAKH

■ NIDHI BAHUGUNA



The most dangerous lie is that which contains some element of truth. China's claim on Ladakh and Arunachal is one such lie, which is based on sophistry. For some time, China has been changing the names of places in Arunachal, so there is a need to counter Chinese claim with irrefutable facts.

The most important fact is that Historically, China never shared a border with India. When there was no border between India and China for centuries, then how can China claim Ladakh and Arunachal of India as part of its territory ?

In 1949, Communist China occupied Sinkiang, named later as the Uyghur Autonomous Province of Xinjiang. Historically this area was called East Turkestan. This

occupation enabled, China to create a border with India at north of Karakoram Pass. By invading Tibet in 1950, China created another border with India at Tibet boundary.

POPULAR ANCIENT NAMES OF CITIES IN CHINESE REGION OF XINXIANG

Major cities in Sinkiang were called by their ancient names of Indian origin upto 1947. The city of Kashgar was called Kashi. The popular ancient name of Yarkhand was Harikhand. There was a small area named Jatpur in Sinkiang. These facts are found in the book 'Kashmir and Kashgar', author A.W. Bellew, which is a description of his journey in 1873-1874. Kashgar also had a Sanskrit name Shrikirti. Ptolemy, the Roman



geographer, addresses Kashgar as 'Kasi'.

INDIAN CLAIMS IN XINXIANG REGION

The boundaries of the kingdom of Emperor Kanishka of the Kushan Empire extended beyond Kashgar and Yarkhand. Kashgar came within the boundaries of the kingdom of Kashmiri emperor Lalitditya. It was from Kashgar that Lalitaditya conquered Gilgit. Till 1947, Taghdambush Pamir and Raskam region were under the sovereignty of Jammu and Kashmir Durbar. After the accession of Jammu and Kashmir with India, these regions became a part of India. Documents from the British in the National Archives confirm ancient Indian rights over these areas. In the file noting of the Defense Department, it is written that the boundary of Jammu and Kashmir extends till Pamir. There are also documents stating tax collection in Raskam and Taghdumbash Pamir. If China makes baseless claims on Arunachal and Ladakh, then India should remind China of Bharat's ancient claims on areas presently under Chinese Occupation.

ANALYSIS OF CHINA'S BASELESS CLAIMS

On September 8, 1959, China issued maps and included Arunachal and Ladakh within China's borders. Arunachal and Ladakh both share a border with Tibet. The question is, why did China do this? It is pertinent to recall, that on March 29, 1959, Dalai Lama came to India to seek refuge. 80,000 Tibetans also came to India to seek refuge. China wanted to erase the identity of Tibet by making it a Chinese province, which was opposed by the Tibetan people. China opposed India's grant of asylum to the Dalai Lama.

Arunachal Pradesh was never a civilizational part of China or Tibet. Arunachal Pradesh is mentioned in the Puranas, Ramayana and Mahabharata. In 1914, the border between Britain and Tibet was drawn and the McMahon Line, marking the border between Arunachal Pradesh (NEFA) and Tibet, was accepted by British India and Tibet. China did not participate in

these talks and did not accept the McMahon Line. In 1936, the British released Survey of India maps which showed Arunachal as part of India.

India became independent in 1947 and Arunachal Pradesh was included in the Indian map. China became independent in 1949. In the 1962 war, China captured Tawang, but after announcing the end of the war on 21 November 1962, China withdrew its army, vacating Tawang and Arunachal. Dalai Lama has also accepted Tawang and Arunachal as an integral part of India in 2007, 2008 and 2011. Against this historical backdrop, China's claim on Arunachal Pradesh lack any weightage.

ANALYSIS OF CHINA'S CLAIMS ON LADAKH

China also laid claim to Ladakh in 1959. The boundaries of Ladakh and Tibet are demarcated in the Treaty of Tingmosgang of 1684. In addition, Minsar region located in Tibet is also mentioned as being under the suzerainty of the Ladakhi King. Minsar is an Indian enclave located near Kailash Mansarovar which since ancient times used to pay taxes to Ladakh, then Sikh Empire, then Jammu and Kashmir state and after its accession, to India. Near Minsar is Teerthpuri, where pilgrims used to take bath in the hot water springs, before going to Kailash Mansarovar. In the Treaty of Chushul between Sikh Empire and Tibet in 1842, the border of Ladakh and Tibet is also demarcated and the rights over Minsar are also stated.

India submitted more than 600 pieces of proof to China in the Sino-Indian border talks (1959–1961) which corroborate Indian claims. But China built a road through The Indian territory of Aksai Chin from 1954. China occupied Eastern Ladakh in October 1962.

In 1954, India gave up its ancient trade and transit rights in Tibet under the Trade and Transit agreement with China normally called Panchsheel. However, Minsar continued



paying taxes to India till 1962, until after the war, when all relations with Tibet were stopped.

China wants to eliminate Tibet's identity and make it a Chinese province. historically, Tibet was a Kingdom with its own special identity. Since ancient times, the area of Kailash Mansarovar was an integral part of Indian civilizational identity. Maurya Empire, Kanishka, Lalitaditya – all secured their frontiers at Tibet.

From Jammu, Zorawar Singh extended the boundaries of the Sikh Empire towards Ladakh. Zorawar Singh's attack on Tibet can be analyzed as an attempt to reclaim Kailash Mansarovar, India's historical heritage. Zorawar Singh stationed his army in Minsar and visited Kailash Mansarovar. finally he lost his life while Fighting the enemy near Minsar. It is necessary, therefore, that a discussion be established on Indian rights over this area.

In 1963, a Sino-Pak boundary treaty was signed between China and Pakistan to demarcate the Xinxiang border. It should be remembered that after India became independent in 1947, Pakistan attacked Gilgit Baltistan and Mirpur Muzaffarabad, illegally occupying the area ever since. Through this illegal occupation, Pakistan created a border with China in the Xinxiang region. In March 1963, Pakistan handed over the Shaksgam valley in Gilgit Baltistan occupied area to China. India opposed this illegal transfer as Pakistan shared no legal border with China. An important fact is that the treaty accepts this area as disputed and states whenever the dispute is resolved, China will enter into a fresh agreement with the sovereign nation.

China claims the Tawang area of Arunachal by saying that it used to pay tribute to Tibet annually. It needs to be understood that By 1950, India had stopped collection and payment of this tribute from the residents. The citizens of Arunachal Pradesh consider themselves Indians and

reject China's sophistry.

In Contrast, Bhutanese enclaves and Ladakhi enclaves have existed in Tibet for centuries. These are Darchen Enclave of Bhutan and Minsar of India. In 1950, a representative from the Ministry of States visited Minsar. It is clearly written in his report that the residents of Minsar consider themselves a part of India and pay their Taxes voluntarily.

China's claims on India are not based on any solid evidence. China also claims Barahoti in Uttarakhand. The tax receipts of the traders who used to go to Tibet from Garhwal are presented as proof. India had tabled a white paper in Parliament in 1961, related to boundary talks and correspondence with China. In relation to Barahoti, the fact was presented that the thumb impression of the Garhwali businessman was taken on the tax slips written in Chinese language, which China considers as proof of its sovereignty over Barahoti.

India has ancient relations with Tibet. Tibet has always been a buffer between China and India. Four rivers of India originate from Kailash Mansarovar region - Indus, Sutlej, Brahmaputra and Karnali (tributary of Ganga), which are an integral part of Indian civilizational identity.

China has invaded Eastern Ladakh and cut off India from Central Asia. By occupying Xinxiang, China has closed the ancient trade routes leading from Leh to Yarkhand. It is necessary for every Indian to understand the strategic importance of the areas occupied by China and Pakistan.

China lays its claim on Arunachal without any concrete evidence. Some time ago it had also claimed Bhutan's Doklam. An attempt was made to infiltrate into Galwan also.

It is necessary that we recall the ancient Indian territories, traditional claims and ancient Indian names of the areas occupied by China and give a factual answer to China's fallacies. ■



पूर्ववर्ती सरकारों ने की राष्ट्रीय हितों के साथ अनदेखी !

क्या भारत के पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण कच्चाथिवू द्वीप पर श्रीलंका ने अपना कब्जा कर लिया? क्या भारत की यह भूमि भी उसी मानसिकता की शिकार बनी, जिस मानसिकता ने पाकिस्तान-बांग्लादेश का निर्माण कराने के साथ ही तिब्बत की भूमि चीन को सौंप दी? क्या भारत के भू-भाग निर्धारण से जुड़े मामलों में पूर्ववर्ती सरकारों ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की? ऐसे कई गंभीर प्रश्न सूचना कानून के तहत प्राप्त हुई उस जानकारी से उठे हैं, जिसमें बताया गया है कि 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति सिरिमाओ भंडारनायके ने एक समझौता किया था, जिसके माध्यम से कच्चाथिवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था।

भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरूमध्य में 280 एकड़ में फैला कच्चाथिवू द्वीप जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, 1974 तक भारत का हिस्सा था, जिस पर अब श्रीलंका का नियंत्रण है। तमिलनाडु में भारतीय तट से उत्तर-पूर्व में लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह द्वीप आर्थिक, सामरिक एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह द्वीप 1.6 किलोमीटर लम्बे और तीन सौ मीटर के भू-क्षेत्र में अवस्थित है।

आरटीआई से मिली जानकारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में तमिलनाडु में होने वाले लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था और इसके पीछे उनके राजनीतिक हित मौजूद थे। कई आधिकारिक दस्तावेज और रिकॉर्ड खुलासा करते हैं कि भारतीय भू-भाग वाले इस द्वीप पर अपने नियंत्रण की लड़ाई को भारत अपनी अदूरदर्शिता, राष्ट्रीय हितों की अनदेखी एवं स्वकेन्द्रित राजनीति के कारण उस छोटे देश से हार गया, जो इसे

छीनने के लिए दशकों से प्रतिबद्ध था। इसका नकारात्मक परिणाम तमिलनाडु के उन लाखों मछुवारों को भुगतना पड़ा, जो अपनी आजीविका के लिए कच्चाथिवू द्वीप क्षेत्र तक जाकर निर्बाध रूप से मछली पकड़ने के लिए स्वतन्त्र थे।

ऐतिहासिक प्रमाण यह बताते हैं कि कच्चाथिवू द्वीप 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानन्द के अधीन था। ब्रिटिश शासनकाल में यह द्वीप मद्रास प्रेसीडेंसी के पास आया। इसके बाद ही भारत की ब्रिटिश सरकार और श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) के मध्य कच्चाथिवू द्वीप को लेकर विवाद की स्थिति बनना आरम्भ हुई। स्वतंत्रता के बाद द्वीप को भारत का हिस्सा माना गया। लेकिन स्वतन्त्र भारत में कई वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले जवाहरलाल ने भारत के इस भू-भाग को अनदेखा किया और भारत सरकार द्वारा इसका कभी सीमांकन नहीं किया गया। इसका लाभ श्रीलंका ने उठाया और अपने दावे पर अड़ा रहा। 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हुए यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। हस्तांतरण की वैधता को एक याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, परन्तु याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद से अब तक यह मामला विवाद का विषय बना हुआ है।

तमिलनाडु सरकार एवं जनता ने कच्चाथिवू द्वीप पर श्रीलंका के नियंत्रण को कभी स्वीकार नहीं किया। विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके निर्णय का विरोध भी किया गया। मछुवारों से जुड़े मुद्दों और उनके हितों को लेकर राज्य सरकार कई बार मुखर तो हुई, पर उसकी मुखरता में छिपे राजनीतिक कारण कच्चाथिवू द्वीप से जुड़े विवादित मुद्दों का कोई समाधान नहीं कर सके। देखना यह होगा कि आरटीआई से सामने आई जानकारियों के बाद भविष्य में क्या कच्चाथिवू द्वीप पुनः भारत की भूमि के हिस्से के रूप से प्रतिष्ठित हो सकेगा? ■

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम

आरजीपीवी में हुए भ्रष्टाचार पर अभावपि का आंदोलन जारी, मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग



भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में आर्थिक भ्रष्टाचार करने वाले दोषियों के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभावपि) ने कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आर्थिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलित अभावपि कार्यकर्ताओं की मांग के बाद गठित जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता उजागर हुई है। लेकिन अब तक दोषियों के विरुद्ध किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न होने से पुलिस की भूमिका भी सवाल के घेरे में हैं।

अभावपि कार्यकर्ताओं ने 31 मार्च को काले कपड़े पहनकर भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव किया और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। प्रशासन द्वारा ध्यान न दिए जाने के बाद गत 7 अप्रैल को अभावपि कार्यकर्ताओं ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास का

घेराव कर दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदर्शन कर रहे अभावपि के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद अभावपि कार्यकर्ता पदयात्रा कर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना-प्रदर्शन कर उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

अभावपि की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा के अनुसार आरजीपीवी विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक के निजी खाते में भेजे गए। प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होने के एक माह बाद भी कोई कार्रवाई का न होना संदेह पैदा करता है। अभावपि मध्य भारत प्रांत के मंत्री संदीप वैष्णव के अनुसार भ्रष्टाचारियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अभावपि चरणबद्ध ढंग से अपना आंदोलन जारी रखेगी।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून

■ अजीत कुमार सिंह

भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। नए कानून के लागू होने के बाद बिना किसी आधिकारिक कागजात के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिन्दू अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019 से जुड़े अधिनियमों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी अंतिम स्वीकृति के बाद गत 12 मार्च को अधिसूचित कर दिया।

नया नागरिकता संशोधन कानून 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई नागरिकों को देश की स्थायी नागरिकता सुनिश्चित करेगा। नागरिकता प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए गृहमंत्रालय ने एक पोर्टल प्रारम्भ कर दिया है। प्रक्रिया के तहत तीन अधिसूचित देशों से भारत आए विस्थापितों से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। हालांकि यह कानून दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुआ था और राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। लेकिन सुनियोजित ढंग से हुए विरोध-प्रदर्शन के कारण नए कानून को अब लागू किया

नया नागरिकता संशोधन कानून 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई नागरिकों को देश की स्थायी नागरिकता सुनिश्चित करेगा। नागरिकता प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए गृहमंत्रालय ने एक पोर्टल प्रारम्भ कर दिया है। प्रक्रिया के तहत तीन अधिसूचित देशों से भारत आए विस्थापितों से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा।



गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019 अखण्ड भारत के उन हिन्दुओं के लिए वरदान के रूप में देखा जा सकता है, जो भारत विभाजन से पूर्व उन क्षेत्रों में निवास करते थे, जिन्हें अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। विभाजन के बाद अस्तित्व में आए तीनों देशों में रहने वाले अधिकांश हिन्दू परिवार भारत नहीं आ सके, जिसके बाद उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण तो किया ही गया, जबरन मतांतरण का शिकार भी बनाया गया।

1947 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश एवं पाकिस्तान) में कथित धर्मनिरपेक्षता एवं भाईचारे के नाम पर जिन हिन्दुओं को रोका गया, उनमें सर्वाधिक दलित वर्ग के थे। दशकों तक धार्मिक उत्पीड़न, अपमान, बलात मतांतरण और रक्त-पात का शिकार होने के बाद तीनों ही देशों में जहां हिन्दुओं की संख्या में कम होती गई, वहीं जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई वर्ग की जनता भी प्रताड़ना का शिकार हुई।

धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार अपनी जान बचाकर भारत चले

नए नागरिकता कानून का देश में निवास करने वाले किसी नागरिक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कानून मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान) से धार्मिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित होकर भारत में शरण लेने वालों लोगों को भारत की नागरिकता सुनिश्चित करेगा।

आए और दिल्ली, राजस्थान जम्मू, कश्मीर, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में लम्बे समय से अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 से पहले किसी भी विस्थापित व्यक्ति को भारत की नागरिकता

लेने के लिए 11 वर्ष देश में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब यह अवधि छह वर्ष कर दी गई है।

यहां समझने वाला तथ्य यह भी है कि नए नागरिकता कानून का देश में निवास करने वाले किसी नागरिक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कानून मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान) से धार्मिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित होकर भारत में शरण लेने वालों लोगों को भारत की नागरिकता सुनिश्चित करेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान चूंकि मुस्लिम देश है, इसलिए वहां मुसलमानों के उत्पीड़न का प्रश्न ही नहीं उठता। नागरिकता संशोधन कानून सिर्फ भारत के तीन करीबी देशों, जिनका अपना राजधर्म है, के छह अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य से लाया गया है।

सीएए लागू होने के बाद शरणार्थियों से मिले अभावपि कार्यकर्ता

केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने की अधिसूचना जारी करने के उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभावपि) कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली स्थित मजनु का टीला क्षेत्र में बने शरणार्थी शिविर में विस्थापित होकर रह रहे हिन्दू शरणार्थियों के साथ एक साथ होली और दीवाली मनाई। शरणार्थियों के बीच उत्साहपूर्वक मिठाईयां बांटी गईं और हवन पूजन के साथ ही जमकर गुलाल उड़ाया गया। अभावपि दिल्ली प्रांत संगठन मंत्री राम कुमार ने कहा कि धार्मिक रूप प्रताड़ित किए जाने के बाद हमारे भाई-बहनों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इनके ऊपर बार-बार भारत से चले जाने की जो तलवार लटकी हुई थी, वह अब पूरी तरह से टल गई है। अब शरणार्थी भाई भारत की नागरिकता लेकर रह सकते हैं। कानून लागू होने से प्रसन्न शरणार्थियों ने कहा कि



हम दशकों से दिल से भारतीय थे। आज इस कानून के लागू हो जाने के बाद भारतीय हो गए हैं और अब हमारे बच्चे भी पढ़-लिख कर सपनों का भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



डा. बी. आर. आंबेडकर : महानता मिथक न बने

■ डा. शिव पूजन प्रसाद पाठक

मारत के स्वाधीनता आन्दोलन में अनुसूचित जाति के नेतृत्व की दृष्टि से तीन धाराएं बहती हुई दिखती हैं। एक धारा का नेतृत्व जोगेंद्र नाथ मंडल कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल के निवासी थे और राजनीतिक रूप से मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। भारत के विभाजन के समय वह पाकिस्तान चले गए और वहां लियाकत अली खान के मंत्रालय में पहले विधि मंत्री बने। यद्यपि शीघ्र ही पाकिस्तान से उनका मोह भंग हो गया और भारत वापस लौट आ गए। जिस दलित और मुस्लिम राजनीति के सामाजिक गठबंधन की वकालत वह कर रहे थे, वह गठबंधन पाकिस्तान में बिखरते हुए दिखाई दिया। इसी तरह दूसरी धारा का नेतृत्व बाबू जगजीवन राम कर रहे थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ थे और उसकी सोच से प्रभावित रहे। बाबू जगजीवन राम की सोच भारत के एकीकरण की सोच थी और पूरी तरह राष्ट्रवादी थी। तीसरी धारा के अगुवा डा. बी.आर. आंबेडकर हैं। डा. आंबेडकर की धारा वैचारिक दृष्टि से विस्तृत और प्रभावी है। इस वैचारिक धारा को राजनीतिक और सामाजिक आधार मिला और स्वतंत्र भारत में डा. आंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में स्थापित हुए। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष हो जाने के कारण डा. आंबेडकर की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हो गई। प्राथमिक शिक्षा के समय उन्होंने अपने पिता की उपाधि 'सकपाल' न लेकर अपने गुरु के आंबेडकर उपनाम को स्वीकार किया। महाराजा बड़ौदा द्वारा उच्च शिक्षा के लिय प्रदत्त छात्रवृत्ति ने भी उनके शैक्षिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्तमान समय में डा. आंबेडकर एक स्तम्भ की तरह हैं, जिनके आस-पास भारत की राजनीति घूमती है। उनके जीवन के कई रूप हैं और कई अवस्थाओं से गुजरे हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। डा. आंबेडकर शिक्षक और सशक्त लेखक हैं। उनके लेखन का फलक

व्यापक है। एक प्रकार से वह तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी हैं। उन्होंने राजनीति, समाज, विधि, विश्व-इतिहास, धर्म, अर्थशास्त्र, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर लेखन गहन अध्ययन के बाद किया। वह एक पत्रकार भी हैं। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत जैसे पत्र और पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने विभिन्न समय में किया। वह विधिवेत्ता और राजनीतिक है। डा. आंबेडकर कुशल संगठनकर्ता हैं। अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और आल इंडिया शेड्यूलड कास्ट्स फेडरेशन का गठन करते हैं। आन्दोलनकर्ता भी हैं। अस्पृश्य समाज की सार्वजनिक स्थलों पर भागीदारी हो, इसके लिए महार सत्याग्रह जैसे आन्दोलन भी करते हैं।

उनके राजनीतिक जीवन को वैचारिक दृष्टि से सामान्य तौर पर दो अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवस्था वह है, जहां डा. आंबेडकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में हैं और ब्रिटिश सरकार या संस्थाओं में पदाधिकारी हैं। उनके चिंतन के केंद्र में अस्पृश्य समाज का हित है। उनके लिए मुस्लिम लीग की तरह पृथक निर्वाचन चाहते हैं। इसलिए किसी के साथ सहयोग ले लेते हैं। अपने चिंतन की दूसरी अवस्था में, जब वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं, तब उनके विचारों में राष्ट्रीयता दिखती है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र का एकीकरण ही उनके चिंतन का आयाम बनता है। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता, भाषा, केंद्र के पास शक्तियों जैसे विषयों पर मुखर और स्पष्ट हैं, जिसमें एक सशक्त भारत की चाह रही है। विधि मंत्री के रूप में पाकिस्तान से अपने समाज के वापस आने का आह्वान हो या इस्लाम न स्वीकार करने की सलाह हो, वह राष्ट्रीय हित को ध्यान देते हैं। यहां पर डा. आंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं और उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ जाती है।

डा. आंबेडकर का चिंतन भी क्रमिक विकास का परिणाम है। समतामूलक समाज के निर्माण की सोच



भारतीय चिंतन परम्परा से ही है। वह प्राचीन और अद्यतन के बीच सामाजिक सुधारक के भाव से एक कड़ी हैं। उनका संघर्ष आत्मसम्मान का संघर्ष है। इस संघर्ष में शिक्षा को अनिवार्य कड़ी के रूप में देखते हैं। चूंकि उनकी उच्च शिक्षा विदेश से ही प्राप्त है, इसलिए उनके चिंतन पर पाश्चात्य विचारों का प्रभाव है और वह उसे श्रेष्ठ भी मानते हैं। डा. आंबेडकर के चिंतन का केंद्र बिंदु सामाजिक सुधार ही है। वह भारतीय सामाज में प्रचलित अस्पृश्यता का अंत चाहते हैं और प्रत्येक स्तर पर इसका प्रतिरोध करते हैं और जनचेतना का प्रसार करते हैं।

वर्तमान समय में आभासी दुनिया की लोकप्रियता एक प्रतीक है। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को सोशल मीडिया एकदम सजी दिखती है। सभी दलों और सामाजिक समूहों के लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यह उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक विवशता का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने डा. आंबेडकर के विचारों के प्रसार एवं प्रचार के लिए उनके जीवन से सम्बंधित स्थान (जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाणभूमि और चैत्य भूमि) को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। सरकार के निर्देशानुसार 26 नवम्बर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। यह उनके संविधान में योगदान की स्वीकारोक्ति है।

आवश्यकता है कि डा. आंबेडकर को समग्रता में पढ़ा और समझा जाए। वह काफी रुचिकर लेखक सिद्ध हो सकते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें केवल सामाजिक न्याय की सीमा में सीमित कर दिया गया है। वह भारत के राजनीतिक आदर्श तो बन गए हैं, लेकिन वह वैचारिक और विद्वत्त्व में बहुत पीछे छूट गए हैं। उनके आर्थिक विचार विशेषकर भारत में विदेशी ऋण की समस्या, केंद्र-राज्य संबंध, इस्लाम पर विचार और शूद्र कौन थे? विदेश और सुरक्षा, मार्क्स और बुद्ध जैसे विषयों को जनमानस के सामने लाना आवश्यक है।

डा. आंबेडकर राजनीति का एक वैचारिक आयाम भी हैं। उनकी सोच और समझ के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। चूंकि राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धी होते हैं। इसलिए उनके विचारों का दुरुपयोग न होने पाए क्योंकि इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा

हुआ है। कार्ल मार्क्स की 1888 में मृत्यु हो गई और उसके विचारों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या के आधार पर एक रक्तरंजित इतिहास मानव समाज ने देखा। बहुत कम लोगों ने ही मार्क्स की मौलिक रचना पढ़ी होगी, लेकिन व्याख्याकारों ने निजी स्वार्थ में मार्क्स के विचारों का उपयोग किया। दूसरा प्रमुख उदाहरण, भारत के सन्दर्भ में महत्मा बुद्ध से है। भगवान बुद्ध को व्याख्या के आधार पर सनातन धर्म के विरोध में खड़ा कर दिया। बौद्ध धर्म का आधार ग्रन्थ त्रिपिटिक है। त्रिपिटिक में सभी वैदिक देवताओं का सकारात्मक उल्लेख है। इसलिए डा. आंबेडकर को भी उनकी मौलिकता और समग्रता में पढ़ने और समझने की आवश्यकता है क्योंकि उनके विचारों के निकट एक मिथक का निर्माण हो रहा है जिसका उपयोग राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किया जा सकता है।

(लेखक नई दिल्ली स्थित डा. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सह-आचार्य हैं।)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अप्रैल 2024 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वपूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें :-

‘राष्ट्रीय छात्रशक्ति’

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.

फोन : 011-23216298

www.chhatrashakti.in

✉ rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com

📘 www.facebook.com/Rchhatrashakti

🐦 www.twitter.com/Rchhatrashakti

📷 www.instagram.com/Rchhatrashakti



महज घटना नहीं, अपितु मानसिकता है संदेशखाली

■ याज्ञवल्क्य शुक्ल

पश्चिम बंगाल के उत्तर चौबीस परगना जिले स्थित संदेशखाली क्षेत्र की हिंदू माताओं-बहनों के साथ वर्षों से हो रहा शारीरिक एवं मानसिक शोषण महज एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक जेहादी मानसिकता का परिलक्षण और उसकी पुनरावृत्ति है। घटना की नियति उसके घटित होने तक ही सीमित होती है, परंतु मानसिकता का स्वरूप घटनाओं की पुनरावृत्ति तक विस्तारित होती है। वर्षों से संदेशखाली की निर्दोष महिलाएं, जिनमें से अधिकांशतः अत्यंत पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग की हैं, जेहादियों के हाथों लैंगिक शोषण, दुराचार, बलात्कार एवं लूट का शिकार हो रही थीं। अपने एवं अपने परिवारों पर हो रहे इस शोषण तथा उत्पीड़न से तंग आकर संदेशखाली से कई परिवारों का पलायन हो रहा था। यदि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दौरा संदेशखाली में नहीं हुआ होता तो यह विभत्स मामला जनमानस के सामने कभी नहीं आता। इस पूरे घटनाक्रम में शर्मता की अति यह रही है कि दोषियों को तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त होता रहा है।

यह सोचने वाली बात है कि महिलाओं को देवी एवं शक्ति के रूप में अंगीकार करने वाली बंगाल की इस पवित्र भूमि में महिलाओं के शोषण, दुराचार तथा उनकी अस्मिता को हनन करने का बीज कैसे अंकुरित हुआ? ऐतिहासिक तथ्य इंगित करते हैं कि संदेशखाली की घटना का बीज पूर्व में घटित समान प्रकार की घटनाओं से पल्लवित है, चाहे वह 1921 का मोपला नरसंहार हो या 1946 में नोआखाली का हिंदू नरसंहार।

खिलाफत आंदोलन की आड़ में केरल के दक्षिण मालाबार में अगस्त 1921 में मोपला मुसलमानों ने उन्हीं हिंदू जमींदारों का कत्लेआम एवं हिंदू महिलाओं से दुराचार का तांडव शुरू किया था, जिनके हिंदू

पूर्वजों ने मोपलाओं को अपनी जमीन एवं संपत्ति देकर उनको अपनी भूमि पर अंगीकृत किया था। मोपलाओं ने अपने आका अठारहवीं शताब्दी के हैदर अली से प्रेरणा लेकर कत्लेआम एवं दुराचार का तांडव इस कदर मचाया कि मालाबार के हिंदू अपनी संपत्ति छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन को मजबूर हो गए। हिंदू-मुस्लिम एकता के रूप में प्रक्षेपित खिलाफत आंदोलन का पटाक्षेप अंततः हिंदुओं के नरसंहार के रूप में हुआ।

हिंदू नरसंहार एवं दुराचार के इस भाव की पुनरावृत्ति अक्टूबर-नवंबर 1946 में तत्कालीन संयुक्त बंगाल के चटगांव डिवीजन के नोआखाली क्षेत्र में देखने को मिली। कई माह तक नोआखाली में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनकी संपत्तियां जबरन छीन ली गई, गांव के गांव मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर दिए गए और लाखों हिंदू अपने परिवार के साथ नोआखाली से विस्थापित होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर किए गए। हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों के इस सुनियोजित आक्रमण ने संयुक्त भारत के अन्य स्थानों पर भी हिंदुओं के नरसंहार एवं पलायन को बढ़ावा दिया, जिसका परिलक्षण भारत विभाजन के रूप में हुआ।

इन सभी घटनाओं में एकरूपता का यह भाव रहा है कि सर्वप्रथम भारत के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी को गैरकानूनी तरीके से बढ़ाया जाए और फिर वहां के बहुसंख्यक हिंदुओं को कत्लेआम करके, उनकी संपत्ति को लूट करके तथा हिंदू महिलाओं की अस्मिता का हनन करके विभत्सका का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए, जिससे हिंदू परिवारों का पलायन हो और अंततः भारत को विभिन्न हिस्सों में विभाजित करने में सफल हो सके।

संदेशखाली की घटना भी जेहादियों के इसी



दुष्चरित्र का आविर्भाव है। बांग्लादेश के साथ संदेशखाली की सीमा होने का लाभ इन जेहादियों ने बखूबी उठाया। विगत वर्षों में संदेशखाली में मुस्लिम घुसपैठियों का प्रवाह ने इसे बंगाल के तीसरे सबसे ज्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रखंड में शामिल करा दिया है। आज यह क्षेत्र आतंकवादियों, तस्करों, एवं अपराधियों का अड्डा बन चुका है। 1981 से 2011 जनगणना के बीच हिंदुओं की जनसंख्या जहां चार प्रतिशत घटी, वहीं मुसलमानों की जनसंख्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से चार प्रतिशत तक बढ़ गई है। क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट देश के औसत वृद्धि से लगभग पचास गुना ज्यादा है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी ताकतें भी अपने कुत्सित हितों को पूरा करने के लिए हिंदुओं की संपत्ति को

खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। संदेशखाली में कानूनी एवं गैरकानूनी तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को हड़पकर, हिंदुओं को प्रताड़ित कर, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार एवं बलात्कार कर हिंदू नरसंहार का पटकथा लिखने का कार्य किया जा रहा है, जिसका पटाक्षेप भारत को फिर से विभाजित करके किए जाने की सुनियोजित साजिश के रूप में सामने आ सकता है। ऐसे में देश के जनमानस से यह अपेक्षा है कि जेहादियों की विस्तारवादी षडयंत्र को भलीभांति समझे और संदेशखाली को आज का नोआखाली बनने से रोके। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में संदेशखाली बनाने का जो कुचक्र चल रहा है, उसपर सजग रहकर भारत के असंख्य विभाजन की साजिश को प्रतिकार करना ही होगा। ■

संदेशखाली

अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग

सं देशखाली घटना में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) लगातार संघर्षरत है। संदेशखाली में हुई घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर गत 5 मार्च को अभाविप कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन किया।

अभाविप के नेतृत्व में डीयू, जेएनयू, जामिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने दिल्ली स्थित बंग भवन पर, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों ने कोलकाता में, मुंबई विश्वविद्यालय परिसर, बीएचयू परिसर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर सहित देश के 800 से अधिक स्थानों पर संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार, जघन्य अपराधों तथा जमीन हड़पने के मामले का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।

धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदेश की राजधानियों, जिला केन्द्रों सहित विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों

एवं युवाओं ने ममता सरकार की विफलताओं की निंदा करते हुए संदेशखाली के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। विरोध-प्रदर्शन के उपरांत अभाविप की इकाईयों ने जिला कलेक्टर तथा सक्षम अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा उच्च स्तरीय जांच, आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, पीड़िताओं को कानूनी सहायता और पलायन रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है।

अभाविप के अनुसार देश की युवा-शक्ति संदेशखाली की घटना से अत्यंत दुखी है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने ममता सरकार के संरक्षण में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से ज्यादती की है, वह अत्यंत शर्मनाक है। देश भर के हजारों छात्रों ने ममता की निर्ममता के विरोध में हुंकार भरी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेताओं की ज्यादती का शिकार हुई महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई में पूरे देश का युवा पीड़िताओं के साथ है। अभाविप राष्ट्रपति से मांग करती है कि संदेशखाली घटना में शामिल आरोपियों तथा उनका संरक्षण करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। ■

राष्ट्रीय छत्रशक्ति टीम



अभाविप के राज्य स्तरीय सम्मेलन में आसू और एनएसयूआई ने फैलाई अराजकता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) असम प्रांत द्वारा गौहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय छात्र नेता सम्मेलन को बाधित करने के लिए कांग्रेस की छात्र इकाई राष्ट्रीय नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और अखिल असम छात्र संघ (आसू) के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए अराजकता फैलाई। इस दौरान अभाविप सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई। छात्रों का कहना है कि अराजकता फैलाने वालों ने अभाविप के बैनर-पोस्टर को नष्ट करने के साथ ही असम गौरव लाचित बरफूकन एवं मां कामाख्या की तस्वीर को फाड़कर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। अभाविप का राज्य स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन

गत 18 मार्च 2024 को गौहाटी विश्वविद्यालय के बिरिंची कुमार बरुआ (बीकेबी) सभागार में किया गया था। अभाविप द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को विफल करने के लिए आसू और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाते हुए अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इसके बावजूद अभाविप कार्यकर्ताओं ने धैर्य का परिचय देते हुए सम्मेलन को जारी रखा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने छात्र नेताओं को राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने असम के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हुए कहा कि असम वह प्रदेश है, जहां मुगल ब्रह्मपुत्र घाटी को पार नहीं कर पाए थे। सरईघाट की लड़ाई में महावीर लाचित

बरफूकन ने मुगलों को हराया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षाविद प्रा. नानी गोपाल महंत ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में छात्रों एवं छात्र नेताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नागालैंड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में छात्र नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया।

अभाविप प्रदेश मंत्री हेरोल्ड मोहन ने बताया की छात्र सम्मेलन का उद्देश्य युवा नेताओं को छात्रों और शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। सम्मेलन के माध्यम से युवा नेताओं को एक साथ आने, अपने विचार साझा करने और अपने और पूरे समाज के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए एक मंच मिला।

आसू और एनएसयूआई का विरोध-प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण

अभाविप असम के प्रदेश मंत्री हेराल्ड मोहन एवं सह मंत्री सीमांत कुमार वैश्य ने कहा कि छात्र सम्मेलन के दौरान आसू और एनएसयूआई ने बौखलाहट में विरोध-प्रदर्शन किया और सम्मेलन में अप्रिय स्थिति उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की। प्रदेश भर के छात्रों पर किए गए हमले एवं दुर्व्यवहार, आसू एवं एनएसयूआई के अलोकतांत्रिक रवैये को दर्शाता है। अभाविप इसका पुरजोर विरोध करती है।

अभाविप ने दर्ज कराई प्राथमिकी

गौहाटी विश्वविद्यालय में गत 18 मार्च को छात्र नेता सम्मेलन के दौरान घटित अप्रिय घटना के बाद गत 19 मार्च को अभाविप ने जालुकबाड़ी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभाविप ने इस संदर्भ में करीब 10 शिकायतें दर्ज कराई है। अभाविप ने जालुकबाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद बैनर, पोस्टर जलाने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मी तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने

कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस कारण उपद्रवियों का मनोबल बढ़ गया और घटना ने बड़ा रूप ले लिया।

विश्वविद्यालय परिसर से आसू के कार्यालय को हटाने की मांग

अभाविप ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में आसू का कार्यालय अवैध रूप से बना हुआ है, जिसे अविलंब हटाया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन को यह बताना चाहिए कि यह कार्यालय किस आधार पर आसू को आवंटित गया? अभाविप ने मांग की है कि यदि विश्वविद्यालय के अधिकारी आसू को कार्यालय बनाने की अनुमति दे सकते हैं, तो असम के सभी जनजातीय और छात्र संगठनों को भी विश्वविद्यालय परिसर में कार्यालय बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।



प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन

अभाविप असम के कार्यकर्ताओं द्वारा गत 18 मार्च को आयोजित छात्र-नेता सम्मेलन में असमिया संस्कृति के प्रतीक लाचित बरफूकन तथा मां कामाख्या के चित्र लगे अभाविप के बैनर को एनएसयूआई एवं आसू कार्यकर्ताओं द्वारा जलाए जाने पर प्रदेश भर में विरोध-प्रदर्शन किया गया। अभाविप ने ऐसे कृत्यों द्वारा अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। अभाविप ने कहा है कि असमिया संस्कृति पर किए गए इस अपमान के विरुद्ध गौहाटी विश्वविद्यालय में अभाविप द्वारा लाचित बरफूकन की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



अभाविप ने देश भर में मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

अं तरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का आह्वान किया गया। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले में 'नारी सशक्तिकरण में समाज का योगदान' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अभाविप दिल्ली की प्रांत छात्रा प्रमुख डा. दीप्ति सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव अपराजिता उपस्थित रहीं।

संगोष्ठी की मुख्य अतिथि डा. दीप्ति सिंह ने नारी सशक्तिकरण एवं महिलाओं का समाज में योगदान विषय पर कहा कि हमारे समाज में महिलाओं का विशिष्ट स्थान है। इनके योगदान के बिना पूर्ण समाज की संकल्पना स्वीकार नहीं की जा सकती। हमें इन्हें सशक्त करने के लिए सार्थक प्रयास कर इन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए।

संगोष्ठी की विशिष्ट अतिथि अपराजिता ने कहा कि हमारे इतिहास और परंपरा में नारियां विशिष्ट रहीं हैं। आदि काल से यह हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग रही हैं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर समाज को हर तरीके से सशक्त किया है। आज के दौर में भी नारियां सतत सशक्त हो रही हैं एवं अपनी प्रतिभा और कौशल से समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

राजस्थान स्थित अजमेर में अभाविप अजमेर महानगर द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गत 12 मार्च से 14 मार्च तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं की विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बैडमिंटन, रंगोली प्रतियोगिता, मेंहदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, रस्साकस्सी जैसी

प्रतियोगिताओं के आयोजन में पांच कैम्पस को चुना गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल, मुख्य वक्ता के रूप में अभाविप राष्ट्रीय मंत्री शालनी वर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में धावक जान्हवी इंदौरा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिता भदेल ने कहा कि नारी कोई अबला नहीं है। यह तो युगों-युगों से इस विश्व को अपने अंदर संजोए हुए हैं। नारी शक्ति के रूप में तो कहीं दुर्गा के रूप में हमेशा आगे रही है।

मुख्य वक्ता शालिनी ने कहा कि राजस्थान प्राचीन काल से ही महिलाओं के नेतृत्व के आधार पर चल रहा है। यहां समय-समय पर अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। हाड़ी रानी, रानी पद्मिनी आदि रानियों ने इस धरा पर जन्म लेकर इसको पावन किया है। कार्यक्रम में तीन सौ से ज्यादा छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।

हिमाचल प्रदेश में अभाविप की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने गत 14 मार्च को यशस्विनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की तमाम नारी शक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रही। कार्यक्रम प्रमुख रिया ठाकुर के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सिरमौरी नाटी, शिमला नाटी, किन्नौर कायंग, चम्बयाली नाटी, भांगड़ा, नाटक, योग प्रदर्शन, संगीत प्रस्तुति आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि शिवांगी खरवाल ने कहा कि अभाविप पिछले 75 वर्षों से महिलाओं के सम्मान के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे सांस्कृतिक नृत्य हिमाचली नाटियों में पुरुषों के समान महिलाएं भी बराबर की भागीदारी देते हुए दिखती हैं। इससे हमारी संस्कृति एकता के भाव का संदेश देती हैं। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में छात्राओं की भागीदारी दर्ज की गई।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम

अमृत महोत्सव समारोह में हुआ कार्यकर्ताओं का सम्मान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) छत्तीसगढ़ का अमृत महोत्सव सम्मेलन रायपुर स्थित मैक कॉलेज के सभागार में संपन्न हुआ। अमृत महोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राम बालकदास महात्यागी महाराज, विशिष्ट अतिथि दिनेश अग्रवाल के साथ अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रा. अमित बघेल, प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा भी उपस्थित रहे। समारोह में अभाविप के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ ही रायपुर महानगर के वर्तमान कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था। समारोह में अभाविप छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और संगठन मंत्रियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बालकदास महाराज ने कहा कि आज अभाविप के 83 वर्षीय कार्यकर्ता भी यहां हैं और युवा कार्यकर्ता भी यहां हैं। राष्ट्र की सामाजिक शक्ति को जगाने में इन कार्यकर्ताओं को शील के साथ-साथ अब तेज भी धारण करना होगा। विशिष्ट अतिथि दिनेश अग्रवाल ने कहा कि हम सभी अपने आनन्दमय कोश को जगाकर दिन-प्रतिदिन स्वयं में सुधार करते हुए राष्ट्रसेवा के कार्य में अथक लगे रहें। इसी



से हम राष्ट्रशक्ति के जागरण के अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि अभाविप के कार्यकर्ता ही इसकी पहचान हैं। समाज जीवन के सभी क्षेत्रों को नेतृत्व प्रदान करना अभाविप का दायित्व है। अभाविप के 75 वर्षों के पूरे होने की प्रसन्नता ही अलग है। इस बात की अधिक प्रसन्नता है कि अभाविप अपने दायित्व का निर्वहन भली-भांति कर रही है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सबसे पुराने कार्यकर्ता के रूप में डा. सुरेंद्र आहलूवालिया भी उपस्थित रहे, जिन्होंने 1958 के समय के अपने अनुभव साझा किया।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम

बदलाव

पीएचडी में प्रवेश के लिए देनी होगी यूजीसी नेट परीक्षा

डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी (पीएचडी) शिक्षा के लिए छात्रों को अब यूजीसी नेट (नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट) परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रभावी होंगे। आयोग का मानना है कि इस निर्णय से छात्रों को पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा।

जानकारी के अनुसार आगामी जून माह में होने वाली यूजीसी-नेट की परीक्षा से नए दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत यूजीसी-नेट की परीक्षा का परिणाम अब तीन श्रेणियों में घोषित किया जाएगा। प्रथम श्रेणी में जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) के साथ पीएचडी में प्रवेश एवं सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य छात्रों को, दूसरी श्रेणी में पीएचडी में प्रवेश के साथ

सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य छात्रों को और तीसरी श्रेणी में पीएचडी में प्रवेश लेने वाले छात्रों को रखा गया है। वर्तमान में यूजीसी नेट का परिणाम दो श्रेणियों में घोषित होता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग ने यह निर्णय गत 13 मार्च को हुई 578वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया।

आयोग का कहना है कि पीएचडी में प्रवेश सम्बन्धी यह निर्णय छात्रों के हितों को ध्यान में रख कर किया गया है। वर्तमान में छात्रों को पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं, जिससे छात्रों पर परीक्षा के साथ वित्तीय दबाव भी पड़ता है। नई व्यवस्था के बाद छात्रों को पीएचडी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो अवसर मिलेंगे। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी-नेट के परिणाम के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने से इसके लिए अलग प्रवेश परीक्षा नहीं करानी होगी।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



वीर सावरकर ने अपने प्रखर दैदीप्य से जलती लौ को बना दिया मशाल

■ ध्रुव कांडपाल

“स्वातंत्र्यवीर सावरकर” फिल्म के एक-एक दृश्य को पेंटिंग की तरह पर्दे पर चित्रित किया गया है। जैसे-जैसे फिल्म आंखों के सामने से गुजरती है, स्वातंत्र्यवीर सावरकर का एक-एक फ्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण होता चला जाता है। फिल्म देखते समय यादृच्छिक सुनाई देने वाली तालियों से महसूस होता है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर फिल्म में प्रत्येक दर्शक के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। यह एक महान क्रांतिकारी की कहानी का प्रभाव है कि फिल्म के दृश्यों पर बजने वाली तालियां पार्श्व संगीत की तरह सुनाई देती हैं।

“स्वातंत्र्यवीर सावरकर” इस राष्ट्र से प्रेम करने वालों के लिए बनाई गई फिल्म है। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह समर्पण की कहानी है। विनायक दामोदर सावरकर के राष्ट्र प्रेम का वह सत्य, जिसे उनके पूरे परिवार ने आत्मसात किया और मुस्कराते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। बड़े भाई गणेश सावरकर ने अपने जीवन का समर्पण कर दिया, सरस्वतीबाई ने अपने परिवार का समर्पण कर दिया, यमुनाबाई ने अपने पति और पुत्र को समर्पित कर दिया, नारायण सावरकर ने अपने बचपन और युवावस्था को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया था।

“स्वातंत्र्यवीर सावरकर” प्रारंभ से ही भारत की अखंडता, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के लिए एकजुट होने के वीर सावरकर के विचार के साथ चलती है। सर्वप्रथम अपने परिवार में जागृति। फिर ‘मित्र मेला’ नामक एक मित्र संघ का निर्माण। मित्र मेला का 1904 में विश्व प्रसिद्ध अभिनव भारत के रूप में उभरना। फर्ग्यूसन कॉलेज में विद्यार्थी जोड़ संगठन

विस्तार। सुदूर लंदन के इंडिया हाउस में रहने वाले विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत कर भारत की स्वतंत्रता हेतु गतिविधियां करना तथा सेल्यूलर जेल के कठोर कारावास में भी कैदियों को एकत्रित कर स्वतंत्रता हेतु रणनीतियां बनाना वीर सावरकर की संगठन शक्ति की दृष्टि को स्पष्ट करता है। सेल्यूलर जेल से मुक्त होने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत को वीर सावरकर का इतना खौफ था कि वह वीर सावरकर को रत्नागिरी में नजरबंद कर उन पर सख्त पहरा रखती थी। यह वीर सावरकर की राष्ट्रीय चेतना थी कि उनके संपर्क में जो आया, राष्ट्रभक्ति से स्वतः भर गया। विलासी जीवन जीने वाले मदन लाल ढींगरा वीर सावरकर की गहन देशभक्ति से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन की ओर केंद्रित हो गए। लेकिन, फिल्म में मदनलाल ढींगरा की सजा से विचलित वीर सावरकर जैसे दृढ़ निश्चयी का निराशा से ग्रसित होकर कुर्सियां-मेज फेंकना थोड़ा अखरता है।

स्वातंत्र्यवीर सावरकर के एक दृश्य में जब वीर सावरकर एक ध्वज तैयार करके मैडम भीकाजी कामा तथा अन्य प्रमुख सदस्यों के समक्ष लाते हैं। उस ध्वज को देखकर मदन लाल ढींगरा कहते हैं कि यह स्वतंत्र भारत का ध्वज है। तब वीर सावरकर अखंड भारत के मानचित्र की ओर इंगित करते हुए कहते हैं- अखंड भारत का ध्वज। और उसके बाद ध्वज में वर्णित सभी धर्मों के चिन्हों एवं रंगों का वर्णन सावरकर के सद्भाव, दूरदृष्टि एवं अखंडता का चित्रण है। “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” सिनेमा के सभी मापदंडों पर बेहतर तरीके से खरी उतरती है। “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” की कहानी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्क्रीनप्ले बेहद लाजवाब है। बड़ी और सच्ची कहानी कहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और



रणदीप हुड्डा तथा उत्कर्ष नैथानी ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। निर्देशक रणदीप हुड्डा की फिल्म “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” का फिल्मांकन और संपादन बहुत बेहतरीन है। एक निर्देशक के तौर पर यह फिल्म रणदीप हुड्डा की पहली फिल्म बिल्कुल भी नहीं लगती। रणदीप हुड्डा ने समसामयिक निर्देशकों की कल्पना से बहुत आगे का सिनेमा बनाकर अपने आप को एक उम्दा निर्देशक के तौर पर साबित किया है। “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” फिल्म इस समय की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है, जो भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

संगीत, संपादन, निर्देशन, वेशभूषा, अभिनय सब बहुत प्रभावित करता है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर फिल्म के कई दृश्य दर्शकों के मन को भीतर तक झकझोर देते हैं। अपने बेटे की मृत्यु के बाद वीर

फिल्म के प्रमुख चरित्रों के साथ-साथ फिल्म में कुछ सेकेंडस के लिए भी आए पात्रों ने अपना प्रभाव दर्शकों पर बखूबी छोड़ा है। खुदीराम बोस का चरित्र भले ही पर्दे पर चंद सेकेंड्स के लिए आता है, लेकिन मात्र 18 वर्ष का वह क्रांतिकारी चेहरा सिर्फ एक फ्रेम से दर्शकों के मन मस्तिष्क में घर कर जाता है।

सावरकर की वेदना भीतर तक झकझोरने वाली है। फिल्म का यह दृश्य अपने अभिनय, पार्श्व संगीत तथा फिल्मांकन द्वारा स्वयं में एक करुण कविता रचता है जो दर्शकों के अंतःकरण को व्यथित करता है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर फिल्म में स्वतंत्रता एवं हिंदू धर्म के उत्थान में बाधा डालने वाले इन बंधनों को तोड़ने वाले दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए समुद्र पार कर इंग्लैंड जाना हो या किसी अन्य देश की सभ्यता को समझने के लिए मांस भक्षण। वीर सावरकर ने उन सभी बंधनों को तोड़ा जो मातृभूमि की स्वतंत्रता और हिंदू समाज के उत्थान में बाधा थे।

अपने हर चरित्र को संपूर्णता के साथ करने वाले

रणदीप हुड्डा वीर सावरकर से अच्छे अन्य किसी फिल्म में नहीं लगे हैं। विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका में रणदीप हुड्डा ने अपने करियर का सबसे उम्दा अभिनय किया है। अमित सियाल शानदार अभिनेता हैं और गणेश दामोदर सावरकर की कठिन भूमिका को उन्होंने बड़ी सहजता से निभाया है। सेल्यूलर जेल में भयंकर यातना सहते हुए भी निष्ठावान क्रांतिकारी का जस्बा अमित के शानदार अभिनय में दिखा है। अमित सियाल का सहज अभिनय और रणदीप हुड्डा की ऊर्जा “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” फिल्म की प्रत्येक धारा को शानदार तरीके से प्रवाहित करता हुआ दर्शकों तक पहुंचाता है। अंकिता लोखंडे के अभिनय में यमुनाबाई सावरकर का धैर्य, स्वतंत्रता को लेकर उनकी प्रतिबद्धता और यमुनाबाई की क्रांतिकारी क्षमता स्क्रीन में मजबूती से देखने को मिलती है। फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका में राजेश खेरा ने अद्भुत अभिनय किया है। “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” फिल्म में उनकी आंखों ने भी अभिनय किया है। फिल्म के बहुत से दृश्यों में राजेश खेरा अपनी आंखों से कई बातों को बखूबी कह देते हैं।

फिल्म के प्रमुख चरित्रों के साथ-साथ फिल्म में कुछ सेकेंडस के लिए भी आए पात्रों ने अपना प्रभाव दर्शकों पर बखूबी छोड़ा है। खुदीराम बोस का चरित्र भले ही परदे पर चंद सेकेंड्स के लिए आता है, लेकिन मात्र 18 वर्ष का वह क्रांतिकारी चेहरा सिर्फ एक फ्रेम से दर्शकों के मन-मस्तिष्क में घर कर जाता है। मदनलाल ढींगरा को कौन भूल सकता है। कुछ मिनट के लिए फिल्म में आए मृणाल दत्त ने अपने अभिनय से मदन लाल ढींगरा को जीवंत कर दिया है। फिल्म देखने के बाद शायद कोई विरला ही होगा जो मदन लाल ढींगरा का नाम भूलेगा। निश्चित ही फिल्म देखने के बाद ज्ञात-अज्ञात इन क्रांतिकारियों के त्याग और समर्पण से जनमानस पुनः जुड़ रहा है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर आज के दौर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है जो अपने साध्य को पूरा करती है। “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” फिल्म का नायक यह अखंड राष्ट्र है और राष्ट्र का भाव इसकी आत्मा।



सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में उभरी अभाविप, मत प्रतिशत 12 प्रतिशत बढ़ा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर उभरा है। जेएनयू को वामपंथी अब तक लाल दुर्ग समझते थे, लेकिन अब इस दुर्ग की दीवारें ढहनी आरम्भ हो चुकी हैं। अबकी बार छात्र संघ चुनाव में अभाविप का बढ़ा हुआ मत-प्रतिशत वामपंथी संगठनों के लिए चिंता का विषय बन चुका है और अभाविप की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है।

अबकी बार हुए छात्र संघ चुनाव में केंद्रीय पैनल में भले ही अभाविप को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उनके मत-प्रतिशत में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। पिछले चुनावों की तुलना में अभाविप को 2024 के छात्र संघ चुनाव में बारह प्रतिशत अधिक छात्रों ने अपना मत दिया, जबकि संयुक्त वाम गठबंधन के मत-प्रतिशत में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। एआईडीएसओ, एआईएसएफ, डीएसएफ, जेएनयूटीएसए, पीएसए, रिजर्वेशन क्लब, एसएफआई, हंड्रेड फ्लावर्स ग्रुप के प्रत्यक्ष समर्थन के बावजूद मत-प्रतिशत में हुई मामूली वृद्धि वाम गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। इतने बड़े संयुक्त गठबंधन के सामने बारह प्रतिशत मतों की वृद्धि छात्रों के बीच बढ़ती अभाविप की स्वीकार्यता को दर्शाता है। काउंसलर चुनाव में लगभग पचास प्रतिशत सीटों पर अभाविप ने जीत दर्ज की है। अभाविप को कुल 18 पदों पर जीत मिली है।

अभाविप जेएनयू के इकाई मंत्री विकास पटेल के अनुसार जेएनयू में अभाविप, चार वामपंथी दलों के गठबंधन के विरुद्ध हमेशा की तरह एक बार फिर से एक एकल विशालतम संगठन के रूप में उभरी है। इस वर्ष अभाविप ने एक अभूतपूर्व छात्रमत संग्रह खड़ा किया है, जिसने जेएनयू में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत दिए हैं।



अभाविप ने जेएनयू में हुए छात्रसंघ चुनावों में विद्यार्थी परिषद पर भरोसा करके बढ़-चढ़ कर मतदान करने वाले छात्रों के प्रति आभार व्यक्त किया है। अभाविप का कहना है कि एक बार फिर से, लेकिन बहुत अधिक बड़े मत के साथ अभाविप जेएनयू में सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में और अधिक शक्तिशाली बन कर उभरा है। इसका श्रेय अभाविप ने छात्रों के विश्वास और छात्रों के लिए वर्ष भर लिए जाने वाले कार्यों को दिया है।

अबकी बार विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू छात्र संघ में अपने 18 काउंसलर दिए हैं जोकि छात्रसंघ की कुल संख्या का लगभग पचास प्रतिशत है। इससे छात्रसंघ द्वारा निर्णयात्मक विषयों में अभाविप का बड़ा हस्तक्षेप रहेगा। माना जा रहा है कि अन्य विजयी काउंसलरों में निर्दलीय छात्रों, जिनका समर्थन अभाविप को रहता है, की बड़ी संख्या भी छात्रसंघ में अभाविप की क्षमता और मजबूत करेगी।

अभाविप जेएनयू के इकाई मंत्री विकास पटेल के अनुसार जेएनयू में अभाविप, चार वामपंथी दलों के गठबंधन के विरुद्ध हमेशा की तरह एक बार फिर से एक एकल विशालतम संगठन के रूप में उभरी है। इस वर्ष अभाविप ने एक अभूतपूर्व छात्रमत संग्रह खड़ा किया है, जिसने जेएनयू में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत दिए हैं।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम

राष्ट्रीय कार्यशाला में नवाचार, उद्यमिता और स्वरोजगार पर मंथन

सविष्कार द्वारा कर्णावती (गुजरात) में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 134 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में कुल छह सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर विषय विचार-विमर्श किया गया। गत 31 मार्च को आयोजित कार्यशाला में देश में नवाचार, उद्यमिता, स्वरोजगार विषय पर युवाओं को संबोधित करते हुए पेटेंट डायरेक्टर-जनरल उन्नत पंडित ने कहा कि देश स्टार्टअप, इनोवेशन, पेटेंट्स के लिए आगामी 15 वर्षों की योजना तैयार कर रहा है। भारत में आज 2014 से बेहतर स्थिति में स्टार्टअप इनोवेशन में आ चुके हैं। गत नौ वर्षों के दौरान भारत में एक लाख से ज्यादा पेटेंट फाइल हुई हैं। भारत के स्टार्टअप आज अमेरिका एवं अन्य बाकी देशों के जैसे लग रहे हैं और प्रत्येक छह मिनट में एक पेटेंट के लिए आवेदन किया जा रहा है।

एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डा. सुनील शुक्ला ने कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसने स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया और कई लोगों को इसके विचारों के साथ जोड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारतीय महिलाएं भी स्टार्टअप में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं। प्रो. संजय वर्मा (आईआईएम अहमदाबाद) के अनुसार किसी स्टार्टअप की सफलता के लिए उसकी मार्केटिंग डिमांड पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एनआईडी के डायरेक्टर डा. प्रवीण नाहर ने युवाओं को उनके बनाए उत्पादों की सफलता के लिए उसकी डिजाइन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया क्योंकि इससे उसकी सफलता निर्भर करती है।

सविष्कार के राष्ट्रीय संयोजक डा. क्रांति सागर मोरे के अनुसार सविष्कार 38 प्रांतों में स्टार्टअप और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कार्यरत है। सविष्कार विद्यार्थी परिषद के उन आयामों में से है, जो स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं को बड़ी

संख्या में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सविष्कार का उद्देश्य है कि विद्यालय, महाविद्यालय में बने प्रोजेक्ट्स को उत्पादों में शत-प्रतिशत परिवर्तित कर पाएं।

युवाओं के लिए स्टार्टअप और नवाचार में अवसर विषय पर आयोजित सत्र में जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक राजीव सिजारिया कहा कि अभी भारत में 113 यूनिकॉर्न हैं तथा भारत को 2047



तक विकसित भारत बनाने के लिए स्टार्टअप और नवाचारों की अहम भूमिका रहने वाली है। अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय स्तर से ही स्टार्टअप और नवाचारों के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरिया की तरह भारत में स्किल इंडिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक जिला, एक उत्पादन से एक ब्लॉक एक उत्पादन तक का सफर तय करके ही विकसित भारत की नींव रखने और उसे सशक्त करने में योगदान दिया जा सकता है। कार्यशाला में 70 छात्र, 20 छात्राओं के साथ 15 प्राध्यापक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



चार दिवसीय 33 वां राज्यस्तरीय सम्मेलन नवी मुंबई में संपन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के गतिविधि आयाम डिपेक्स का चार दिवसीय 33वां राज्यस्तरीय सम्मेलन नवी मुंबई स्थित टेरा ना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, एआईसीटीई चेयरमैन टी. जी. सीताराम, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, स्थानीय विधायक गणेश नाईक, डिपेक्स चेयरमैन सुरेश हवारे, स्वागत समिति मंत्री रामनाथ महात्रे, अभाविप प्रांत उपाध्यक्ष वी. डी. कैलाश सोनमानकर, प्रदेश मंत्री संकल्प फलदेशाई, डिपेक्स संयोजक ऋषिकेश पोत्दार ने दीप प्रज्वलित कर किया।

नवी मुंबई स्थित टेरा ना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गत 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित यह सम्मेलन महाराष्ट्र एवं गोवा प्रदेश के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी मेला के रूप में सामने आया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार देश के युवाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने

पर जोर दे रही है। डिपेक्स महाराष्ट्र के छात्रों को विश्व मंच पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार डिपेक्स में सर्वश्रेष्ठ 25 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

सम्मेलन में अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि अभाविप युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में मोड़कर भारत को पावरहाउस बनाने के लिए काम कर रही है। एआईसीटीई के चेयरमैन डॉ. टी. जी. सीताराम ने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में इनोवेटर्स का योगदान अधिक होने वाला है। इसलिए देश की युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी क्षमता से भारत को शीर्ष पर ले जाने में योगदान देना चाहिए। स्थानीय जन प्रतिनिधि गणेश नाईक ने कहा कि अभाविप डिपेक्स जैसी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक मंच प्रदान कर रही है। छात्र संगठन द्वारा इस तरह की पहल करना सराहनीय है। सम्मेलन में स्वागत भाषण प्रसिद्ध उद्यमी सुरेश हवारे ने दिया, वहीं कोंकण प्रांत के मंत्री संकल्प फलदेशाई ने



अभाविप की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इससे पहले स्व. जयन्त सहस्त्रबुद्धे प्रदर्शनी का उद्घाटन डा. होमी. जे. भाभा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति डा. रजनीश कामत ने किया। इस अवसर पर स्वागत समिति के सह मंत्री नीलकंठ बिजलगांवकर, अभाविप कोंकण प्रांत के सह मंत्री राहुल राजोरिया मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर कुलपति कामत ने कहा कि छात्रों की सोचने की क्षमता बढ़ाने वाली प्रदर्शनी अभाविप के माध्यम से की गई है।

सम्मेलन के समापन सत्र में चयनित परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। इस सत्र में अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के निदेशक ए. राजराजन, अभाविप महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, डीटीई के निदेशक विनोद मोहितकर, अजंता फार्मा के उपाध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, डीपेक्स स्वागत समिति अध्यक्ष सुरेश हवारे, सृजन के ट्रस्टी आशीष उत्तरवार, अभाविप कोंकण प्रांत अध्यक्ष श्रीकांत दुदिगकर, प्रदेश मंत्री संकल्प फलदेशाई, टीएसवीके प्रांत संयोजक श्रेया कांसे उपस्थित थे।

इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार महाराष्ट्र में आगामी शैक्षणिक वर्ष से इंजीनियरिंग की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में शोध के बारे में बेहतर सोचा जाता है। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका है, देश के युवा देश के विकास और प्रगति के लिए सोच रहे हैं। डिपेक्स एक आंदोलन है जो नए शोधकर्ताओं को एक मंच प्रदान करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के निदेशक ए. राजराजन ने कहा कि युवाओं को उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शोध करना चाहिए। भारतीय ज्ञान प्राचीन काल से ही उन्नत था, खगोल विज्ञान, वास्तुकला जैसे विभिन्न विषयों में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा था। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि युवाओं को परंपरा और प्रौद्योगिकी को मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में शोध करना चाहिए। अजंता फार्मा के उपाध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि डीपेक्स उद्योग और शिक्षा जगत का एक संयुक्त उद्यम है। अभाविप डीपेक्स के माध्यम से छात्रों के लिए उद्योग क्षेत्र के दरवाजे खोलने का काम कर रही है।

General Championship Award: Sharad Institute Of Technology College of Engineering, Ichalkaranji

MSBTE Award : Walchand College Of Engineering, Sangali

Shodh Award : Shree Vitthal Edu. And Research Institute College Of Engineering (Polytechnic), Pandharpur

Women Award for Technological Innovation (WATI) : Gramin Polytechnic, Nanded

Best Industry Sponsored Project : Government Polytechnic, Nashik

समापन सत्र का संचालन कोंकण प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत डुडगीकर ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कोंकण प्रदेश के मंत्री संकल्प फलदेशाई ने किया।

चार दिवसीय डीपेक्स सम्मेलन में इंजीनियरिंग और सतत भविष्य, 'वित्त प्रबंधन कैसे करें', 'राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका-2047' एवं बदलते 'औद्योगिक परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका' विषय पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन में 1255 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र एवं गोवा के इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा छात्रों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिसे 50 से अधिक उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा चयनित करके 280 प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया गया। पहली बार आईटीआई के प्रोजेक्ट को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें 28 जिले के 137 कॉलेज से 54 प्रोजेक्ट प्राप्त हुए।

जानकारी हो कि डीपेक्स का आरम्भ 1986 में हुआ था। डीपेक्स के माध्यम से महाराष्ट्र और गोवा राज्य के अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग), प्रौद्योगिकी, कृषि के छात्रों के प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 38 वर्षों से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों के नवाचारों के लिए एक मंच प्रदान करना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और छात्रों के तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



भारतवासियों के डीएनए में है सेवा भाव : एस. बालकृष्ण



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रकल्प सेवार्थ विद्यार्थी (एसएफएस) की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन गत 19 एवं 20 मार्च को उदयपुर स्थित नारायण सेवा संस्थान में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सुरमन संस्थान के संस्थापक एवं प्रा. यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार विजेता मनन चतुर्वेदी, अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण, सेवार्थ विद्यार्थी प्रमुख भवानी शंकर एवं संयोजक मुस्कान आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला में मनन चतुर्वेदी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सेवा, संस्कार सदैव संस्कृति और धर्म का विषय है। सेवा करने पर असीम आत्मसंतुष्टि मिलती है। समाज के हर क्षेत्र में सेवा की आवश्यकता होती है। सेवा करने के लिए हमें विजन

और ज्ञान के साथ निःस्वार्थ भाव से समर्पित होने की आवश्यकता है। सेवा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा सूरज के ताप की तरह होना चाहिए और अंधेरी रात में चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होना चाहिए।

अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण ने कहा कि अपनी स्थापना के साथ ही अभाविप अनेक प्रकार के सेवा कार्य करते आया है और सेवा के महत्व को समझते हुए ही सेवार्थ विद्यार्थी को एक गतिविधि के तौर पर स्थापित किया। आज सेवार्थ विद्यार्थी के माध्यम से हम समाज के हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। सेवा हम भारतीयों के लिए सीखने का विषय नहीं है, यह हमारे डीएनए में है। निःस्वार्थ सेवा से अनंत आनंद की अनुभूति होती है। संवेदना से समरसता और हमारे राष्ट्र को जो पहचान है हमारे अष्टादश पुराण सार है - अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

अर्थात् महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का निचोड़ कुल दो ही बातों में रखा। पहला दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरा यह कि दूसरों को अपनी वजह से दुःखी करना ही पाप है।

उदघाटन सत्र के बाद सेवा क्यों, किसकी और कैसे करना चाहिए? विषय पर भाषण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र को संबोधित करते हुए सेवा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुधीर कुमार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सेवा भारती, अभाविप एवं सेवार्थ विद्यार्थी के माध्यम से किए जा रहे सेवा कार्यों से सभी कार्यकर्ताओं को परिचित कराते हुए कहा कि सेवा हमारे जीवनचर्या में शामिल होनी चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सेवा से अछूते रह गए हैं, जिसमें कुष्ठ रोगी, किन्नर समाज, सेक्स वर्कर, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए शरणार्थी इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। भाषण सत्र के उपरांत चर्चा का आयोजन और फिर लाइव सेशन का आयोजन किया गया। लाइव सेशन में विशेषज्ञ के रूप में प्रा. यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार विजेता मनन चतुर्वेदी एवं वैभव भंडारी उपस्थित रहे। दोनों सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं के जिज्ञासाओं का समाधान किया एवं सेवा के विविध रूपों से परिचित कराया। इस अवसर पर सेवार्थ विद्यार्थी से जुड़े वृत्त चित्र को प्रदर्शित किया गया। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संयोजक

किरुथिका अयोदौरे – दक्षिण क्षेत्र संयोजक
दुर्गेश साठवने – पश्चिम क्षेत्र संयोजक
त्रितिका शर्मा – मध्य क्षेत्र संयोजक
अरुणव दत्ता – पूर्वी क्षेत्र संयोजक
दीवाकर आचार्य – पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र संयोजक
कमलेश भट्ट – पश्चिमी उत्तर प्रदेश – उत्तरांचल क्षेत्र संयोजक
यश कुमार सिंह – उत्तर-पश्चिम क्षेत्र संयोजक
अंकुश वर्मा – उत्तर क्षेत्र संयोजक

प्रकल्प समन्वयक

रक्त निर्देशिका – अपराजिता
राइट्स फॉर ब्लाइंड – दुर्गेश साठवने
पुस्तक, लेख एवं सेवा कहानियां – डा. जाह्नवी ओझा एवं किरुथिका अयोदौरे
संवेदना (सेवा इंटरनेशनल) – अदिति पांथरी
सोशल मीडिया – त्रितिका शर्मा
कार्यालय मंत्री – यश कुमार सिंह

कार्यशाला के दूसरे दिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेवार्थ विद्यार्थी की आगामी योजना एवं कार्य स्वरूप पर चर्चा की गई। बैठक में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान भी उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सेवार्थ विद्यार्थी से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंदों की सेवा करने का आह्वान किया। अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा ने सेवार्थ विद्यार्थी से संबंधित प्रबंधन से जुड़े विषय पर चर्चा की। कार्यशाला के अंतिम सत्र में सेवार्थ विद्यार्थी के प्रमुख भवानी शंकर ने दो दिवसीय कार्यशाला से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करते हुए प्रकल्प की आगामी योजनाओं को सामने रखा। कार्यशाला में सेवार्थ विद्यार्थी के क्षेत्रीय संयोजकों की घोषणा भी की गई।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम





राष्ट्रीय बैठक में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम एग्रीविजन की दो दिवसीय बैठक का आयोजन झांसी स्थिति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में हुआ। बैठक में राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा होने के साथ ही कृषि प्रधान देश को कृषि उद्यमिता देश बनाने की दिशा में मंथन किया गया। साथ ही वर्तमान शैक्षणिक स्थिति, छात्रों को रोजगार एवं कृषि क्षेत्र में स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने की प्रेरणा आदि विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कृषि सम्बन्धी विभिन्न तकनीकी पक्ष पर चर्चा के साथ ही इस क्षेत्र में इंटरनेशनल आयोजित करने का विचार भी सामने आया।

एग्रीविजन के कार्यों में हो रहा है विस्तार : निखिल रंजन

एग्रीविजन के दो दिवसीय अखिल भारतीय बैठक का उद्घाटन गत 30 मार्च को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय

कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलगुरु डा. ए. के. सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री (बिहार-झारखंड) निखिल रंजन, उद्यानिकी आयुक्त (भारत सरकार) डा. प्रभात कुमार, एग्रीविजन राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रमुख डा. रघुराज किशोर तिवारी एवं राष्ट्रीय संयोजक शुभम सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अभाविप क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने कहा कि एग्रीविजन के कार्यों का लगातार विस्तार हो रहा है। इसे और वृहत स्वरूप देने के लिए हमें इस विषय को संगठनात्मक रूप में लाने की आवश्यकता है। साथ ही नियमित रूप से इस विषय को लेकर आभासी एवं प्रत्यक्ष बैठक भी होनी चाहिए। कृषि महाविद्यालयों में एग्रीविजन के माध्यम से विद्यार्थी हितों के लिए संघर्ष एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण के निमित्त कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। सभी कैम्पस में अनेक गतिविधियों जैसे विकासार्थ विद्यार्थी, राष्ट्रीय कला मंच, राष्ट्रीय खेल कार्य, सेवा कार्य के लिए भी छात्रों को प्रेरित करना चाहिए।

एग्रीविजन के प्रयासों से कृषि शिक्षा को मिली मान्यता : रघुराज किशोर तिवारी

एग्रीविजन के राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रमुख डा. रघुराज किशोर तिवारी ने कृषि शिक्षा में एग्रीविजन के कार्यों के योगदान के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एग्रीविजन के प्रयासों के कारण ही कृषि शिक्षा को पेशेवर डिग्री के रूप में मान्यता मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एग्रीविजन द्वारा प्रेषित किए गए अधिकतम सुझावों को यथावत शामिल किया गया। शिक्षाविदों में राष्ट्र सेवा का भाव और अधिक बड़े उसके लिए एग्रीविजन निरंतर कार्यरत है।

प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित हो शोध : डा. प्रभात कुमार

उद्यानिकी आयुक्त डा. प्रभात कुमार ने किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि देश में छोटे, सीमांत एवं बड़े किसानों के संसाधनों में अत्यधिक भिन्नता है, जिसके कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके संसाधनों के अनुरूप नीतियां बनानी होगी। साथ ही प्राकृतिक एवं जैविक खेती के क्षेत्र पर केन्द्रित शोध की आवश्यकता है। स्थानीय उत्पाद एवं उनके प्रसंस्करण पर जागरूकता अभियान लेकर उन्हें पहचान मिले, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए।

उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता : डा. ए. के. सिंह

रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डा. ए. के. सिंह ने एग्रीविजन के कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं शोध क्षेत्र में उभरते भारत की उपलब्धियों तथा अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए अधिक एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित करने की आवश्यकता है।

नवाचार का माध्यम बने एग्रीविजन : प्रफुल्ल आकांत

बैठक के दूसरे दिन अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री

प्रफुल्ल आकांत ने एग्रीविजन की आगामी दिशा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विविध राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रान्त सम्मेलनों के माध्यम से एग्रीविजन कार्य का विस्तार तो कर ही रहे हैं। लेकिन एग्रीविजन कृषि महाविद्यालयों में नवाचार तथा मास एक्टिविज्म का माध्यम बने, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। एग्रीविजन के माध्यम से सेवा, विकासार्थ विद्यार्थी, खेल एवं कला जैसी गतिविधियों की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी पहुंचना महत्वपूर्ण बात है। कृषि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए ताकि अपने-अपने विषय क्षेत्र में कृषि विद्यार्थियों में नेतृत्व विकसित हो।

भारतीय कृषि परिषद का हो गठन : शुभम सिंह पटेल

एग्रीविजन राष्ट्रीय संयोजक शुभम सिंह पटेल ने शैक्षिक परिदृश्य के मुख्य विषय पर जोर देते हुए कहा कि ए.एस.आर.बी.- नेट वर्ष में दो बार होनी चाहिए, भारतीय कृषि परिषद् का गठन हो ताकि कृषि शिक्षा में आ रही अनियमितताओं पर रोक लगे और समानता आ सके, विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती अति शीघ्र होनी चाहिए, जिससे शिक्षा एवं शोध का उच्च स्तर बना रहे। उन्होंने उद्यानिकी एवं वानिकी विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी बराबर अवसर प्राप्त होने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

प्रारंभ होगी इंटरनशिप

बैठक के दौरान स्वावलंबन विषय पर प्राध्यापक डा. नितिन गुप्ता एवं डा. जयंत उत्तरवार ने विषय रखा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एग्रीविजन विविध विषयों को लेकर इंटरनशिप प्रारंभ करेगा, जिससे विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सके। इंटरनशिप में विविध विषय रख सकते हैं जैसे-मशरूम उत्पादन, नर्सरी मैनेजमेंट, लैंडस्केपिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, एग्रो कंसल्टेंसी सेंटर, टिश्यू कल्चर, फिशरी, वेटरनरी साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री आदि। एग्रीविजन विविध प्रांतों में विविध विषय पर सात से दस दिन की इंटरनशिप का आयोजन करने की योजना तैयार कर रहा है। ■

राष्ट्रीय छत्रशक्ति टीम

राष्ट्ररंग सहित कई आयोजनों में छात्र-छात्राओं ने दिखाई सृजनात्मक क्षमता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आयाम राष्ट्रीय कला मंच एवं संस्कृति विभाग (उत्तर प्रदेश) के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय 'राष्ट्ररंग' का आयोजन गत 13 से 15 मार्च के मध्य किया गया। मुजफ्फरनगर स्थित लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित राष्ट्र रंग में आर्टिस्ट कैम्प, मूर्ति कला आर्टिस्ट कैम्प, पोर्ट्रेट डेमो क्लास, छात्र-छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता, कलश सज्जा प्रतियोगिता, कविता पाठ, नृत्य प्रतियोगिता कराए गए। इस अवसर चित्रों की प्रदर्शनी एवं क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 6000 वर्ग फीट की रंगोली आकर्षण का केन्द्र बना। इस रंगोली को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने का आवेदन किया गया है।

राष्ट्रीय कला मंच के राष्ट्रीय प्रमुख प्रदीप मेहता ने कहा कि कलाकार की तूलिका से निकला हुआ चित्र एवं गायक के गीतों से तथा रंगमंच के कलाकारों के अभिनय से समाज अपने-आपको सदियों तक उन विचारों को सदैव एक माला के रूप में धारण किए रखता है। राष्ट्रीय कला मंच, राष्ट्रीय सह संयोजक अभिनवदीप ने कहा ऐसे कार्यक्रमों को कला मंच लगातार कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि कलाकारों की प्रतिभा का विकास हो सके। कार्यक्रम के संयोजक मनोज सिंह ने बताया कि राष्ट्र रंग में प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न उत्कृष्ट संस्थानों से कलाकारों ने भाग लिया। यहां प्रतिभागी विद्यार्थियों को तीन दिन तक कला के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय कला मंच द्वारा हर वर्ष ललित कला के विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राष्ट्ररंग का उद्देश्य ललित कला के माध्यम से आम जनमानस के बीच राष्ट्र प्रेम के भाव का अलख जगाने का कार्य किया जाता है। अपनी माटी अपना देश अपनी संस्कृति को दर्शाया जाता है। इस वर्ष इसकी अध्यक्षता



मेरठ प्रांत के द्वारा की गई।

राष्ट्रीय कला मंच एवं राज्य ललित कला अकादमी, संस्कृति मंत्रालय (उत्तर प्रदेश) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्ररंग कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, मुख्य अतिथि के रूप में आलोक स्वरूप, विशिष्ट अतिथि ललित अग्रवाल, अभाविप क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा, राष्ट्रीय कला मंच के अखिल भारतीय प्रमुख प्रदीप मेहता एवं राष्ट्रीय सह संयोजक अभिनवदीप प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 600 छात्र-छात्रा कलाकारों ने प्रतिभाग लिया।

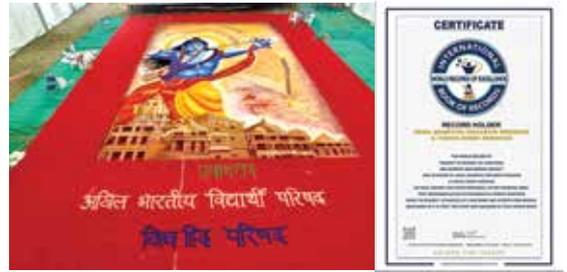
भुवनेश्वर में प्रतिभा संगम का आयोजन



राष्ट्रीय कला मंच द्वारा भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्रांगण में 16-21 मार्च तक कला महापर्व 'प्रतिभा संगम' का आयोजन किया गया। प्रतिभा संगम-2024 के माध्यम से कॉलेज स्तर से जिला स्तर, जिला स्तर से राज्य स्तर तक के प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया। कार्यक्रम का मूल आधार प्रशिक्षण-प्रतियोगिता-प्रदर्शन इन तीन बिंदुओं पर आधारित था। एकल संगीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल अभिनय, समूह एक्ट, ड्राइंग, रंगोली, कविता पाठ, पारंपरिक वेशभूषा प्रदर्शन जैसी कुल नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यंग्य कवि ज्ञान होता ने की, जबकि संचालन नरसिंहनाथ नंदा ने किया। परिचयात्मक भाषण में अभाविप ओडिशा प्रांत अध्यक्ष गार्गी बनर्जी, प्रांत मंत्री अरिजीत पटनायक, प्रांत संगठन मंत्री बैलोचन साहू उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनेता सिद्धांत महापात्रा, पुषिंदर सिंह, समरेश रौथराई, बुलु दास, प्रोड्यूसर श्रीधर मार्था, प्रोफेसर प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय कला मंच के राष्ट्रीय संयोजक गुंजन ठाकुर, सहसंयोजक प्रियरंजन राउत उपस्थित थे। छात्रों को उन्मुख करने के लिए आयोजित प्रथम सत्र को अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री गोविंद नायक और राष्ट्रीय कला मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ध्रुव कांडपाल ने संबोधित किया। प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए और निर्णायक की भूमिका में संगीतकार मन्मथ मिश्रा, शैलभामा महापात्रा, विष्णुमोहन कवि, बैद्यनाथ

दास, कोरियोग्राफर राकेश देव, जया विश्वास, मृतुंजय पांडा, अभिनेता जीवन पांडा, भासवती बसु, मनीषा रथ, कलाकार मिनकेतन पटनायक, उत्कल गुरम नंद, चिंतामणि विशाल, कवि शुभ कुमार दास, गौरप्रिया दास, संजय पांडा, जूही अग्रवाला, श्वेता अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से 800 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

त्रि-आयामी रंगोली बनी विश्व की सबसे बड़ी रंगोली



भगवान श्रीरामलला विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रयागराज में बनाई गई "प्रभुश्रीराम एवं अयोध्या मंदिर" की त्रि-आयामी (श्री-डी) रंगोली विश्व की सबसे बड़ी रंगोली के रूप में वैश्विक स्तर पर सराही गई गई है। गत 22 जनवरी को बनाई गई इस रंगोली को अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकार्ड्स में शामिल करके विश्व की सबसे बड़ी रंगोली होने का प्रमाण पत्र मिला है। यह रंगोली अभाविप के आयाम राष्ट्रीय कला मंच द्वारा बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही प्रशंसा से अभाविप कार्यकर्ता उत्साहित हैं।

अभाविप काशी प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह के अनुसार अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अभाविप द्वारा बनाई गई त्रि-आयामी रंगोली को विश्व की सबसे बड़ी रंगोली के रूप में दर्ज किया गया है। इसका प्रमाण पत्र गत 4 अप्रैल को मिला। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकार्ड्स ने इसे अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी कर दिया था।

जानकारी हो कि प्रयागराज में बनाई गई त्रि-आयामी रंगोली 50 गुना 30 फीट के आकार की थी, जिसे 321 किलोग्राम प्राकृतिक रंगोली रंग से अभाविप इलाहाबाद

मुंबई में राष्ट्रीय छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन

राष्ट्रीय कला मंच विगत वर्षों से सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर करता आ रहा है। देश के विभिन्न स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बीच सिनेमा के निर्माण और निर्देशन के प्रति उनकी सृजनशीलता को एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य राष्ट्रीय कला मंच नेशनल स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से करता आया है। इस वर्ष एनएसएफएफ का आयोजन गत 16 एवं 17 मार्च को मुंबई विश्वविद्यालय स्थित कलीना कैम्पस में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी सिनेजगत के जाने माने निर्माता तरुण राठी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने कलाकारों का मार्गदर्शन किया। महोत्सव में पेन इंडिया लिमिटेड के संस्थापक एवं फिल्म निर्माता जयंती लाल गड़ा भी उपस्थित थे। दो दिवसीय समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आई क्षेत्रीय भाषा की फिल्में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। सत्यजीत मंडले, फिल्ममेकर मुस्ताक नाडियावाला, सिनेमेटोग्राफर असीम बजाज ने मास्टर क्लास लिया। राष्ट्रीय कला मंच के अखिल भारतीय प्रमुख प्रदीप मेहता और संयोजक गुंजन ठाकुर जी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कला मंच के कार्यपद्धति के बारे में प्रतिभागियों से बातचीत करके उन्हें कला के माध्यम से एक सभ्य और शिक्षित समाज के निर्माण हेतु प्रेरित किया। आयोजन में पश्चिम क्षेत्र के संगठन मंत्री देवदत्त जोशी और नगर मंत्री निधि गाला ने भी प्रतिभागियों से संवाद किया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली उपस्थित थे। उन्होंने युवा प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। कस्तूरी कुलकर्णी के द्वारा बनाई गई उन्मुक्त को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए चयनित किया गया और और एक



लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। महोत्सव में देश के लगभग तीन सौ युवा छात्र फिल्म निर्माता शामिल हुए, जिसमें नौ भाषाओं में बारह राज्यों की कुल 35 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा/कहानी का पुरस्कार भोपाल की “बापू की गाड़ी” और वर्धा के “कालाहा” (संस्कृत लघु फिल्म) को मिला। लखीमाई (रांची) और नेक्सट स्टॉप फॉक म्यूजिक (धर्मशाला) को श्रेष्ठ लघु फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया गया। श्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के रूप में आइना (मुंबई) को, श्रेष्ठ संगीत/ध्वनि के रूप में फेथ ऑफ त्रिशुला (मुंबई), श्रेष्ठ निर्माता (प्रोडक्शन) के रूप में 4 डी (हैदराबाद), श्रेष्ठ निर्देशन/संपादन के लिए फ्लाइंग व्हील्स (पुणे) एवं श्रेष्ठ अभिनय के लिए कन्फेशन (बेंगलुरु) को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा जूरी ने छह अनुकरणीय फिल्मों के रूप में ‘टम्ब्रेल’, ‘म्हातरा डोंगर’, ‘हैप्पी दुसेहरा’, ‘आभास’, ‘फोटोफाइल’ और ‘एक दिन की बात’ का उल्लेख किया। आयोजन के दौरान जूरी के रूप में कला जगत के दिग्गज डा. अनुराधा सिंह, असीम अरोड़ा, तेजस देउस्कर, मानस चौधरी दा उपस्थित रहे। विभिन्न श्रेणी में श्रेष्ठ फिल्मों को पच्चीस हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम

विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई थी। इसकी रचना 24 छात्र-छात्राओं ने की थी, जिनकी सहायता 16 अन्य कार्यकर्ताओं ने की थी। रंगोली को माघ मेला परिक्षेत्र स्थित विश्व हिन्दू परिषद के शिविर स्थल में बनाया गया था।

कानपुर में पांच दिवसीय अकल्पित मेधा का आयोजन

राष्ट्रीय कला मंच द्वारा कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक महोत्सव 'अकल्पित मेधा' का आयोजन किया गया। 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित चार दिवसीय महोत्सव में वाद-विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, आकृति बुक कवर, अन्वेषण ट्रेजर, ताल, टक्करहंट, बैंड बैटल, संस्कृत नेट प्रतियोगिता सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत भर के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।



'अकल्पित मेधा' सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, राष्ट्रीय कला मंच की राष्ट्रीय संयोजक कु. गुंजन ठाकुर, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. अनिल कुमार यादव, प्रांत संयोजक भारती प्रजापति की उपस्थिति रही। अकल्पित मेधा के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा विविध कला के क्षेत्र में प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम

उपलब्धि

एक मिसाइल-कई लक्ष्य : भारत ने हासिल की एमआईआरवी क्षमता

मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास एमआईआरवी (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल) क्षमता है। अभी तक यह क्षमता अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन के पास थी। गत 11 मार्च को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एमआईआरवी प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि-5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान का परीक्षण किया। मिशन दिव्यास्त्र नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा स्थित डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। परीक्षण के दौरान विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने अनेक री-एंट्री व्हीकलस को ट्रैक और मॉनिटर किया। इस मिशन ने निर्दिष्ट मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली

टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) उस तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। जिससे दुश्मन के अलग-अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। डीआरडीओ के अनुसार यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता सेंसर पैकेजों से सुसज्जित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पुनः प्रवेश करने वाले वाहन वांछित सटीकता के भीतर लक्ष्य बिंदुओं तक पहुंचें। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति की प्रतीक है। जानकारी हो कि स्वदेश निर्मित अग्नि-5 मिसाइल पांच हजार किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। इसे देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम



NATIONWIDE PROTESTS AGAINST LEFTIST VIOLENCE

On 12th March, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) staged protests across university campuses nationwide following the tragic suicide of a student from Kerala, Siddharthan, who faced severe harassment by goons affiliated to the Students' Federation of India (SFI). The Karyakartas of ABVP held protests at various universities including Banaras Hindu University, Delhi University, Osmania University, Hyderabad Central University, Rajasthan University, Annamalai University and Gujarat University demanding action against those responsible for Siddharthan's suicide.

ABVP condemns the violence perpetrated by SFI criminals and polluting the academic environment with the severe violence and brutality. J.S. Siddharthan, a second-year student at Kerala Veterinary and Animal Sciences University, was subjected to brutal assault by SFI criminals, resulting in severe injuries and humiliation before he tragically took his own life. ABVP demands immediate action against the perpetrators and provides justice to Siddharthan and his family. Despite repeated incidents of violence and intimidation by SFI criminals, there has been a lack of concrete action by the authorities, which is unfortunate and deeply concerning.

ABVP National General Secretary, Yagywalkya Shukla, said that ABVP condemns the Kerala government for failing to protect educational institutions from rampant violence, corruption, and hooliganism perpetrated by SFI criminals. The suicide of Siddharthan has shaken the conscience of the nation and exposed

the deep-rooted problem of ragging in Kerala's educational institutions. Students from various universities who participated in today's protests expressed solidarity with Siddharthan's family and condemned the Kerala government for allowing educational institutions to become a breeding ground for leftist violence.

ABVP National Secretary, Shraavan B Raj, stated, "ABVP had demanded a thorough investigation into Siddharthan's death through protests and hunger strikes outside the Wayanad campus and the Kerala Secretariat. Siddharthan's parents have insisted that his death be treated as murder rather than suicide, and ABVP supports

ABVP NATIONAL GENERAL SECRETARY, YAGYWALKYA SHUKLA, SAID THAT ABVP CONDEMNS THE KERALA GOVERNMENT FOR FAILING TO PROTECT EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM RAMPANT VIOLENCE, CORRUPTION, AND HOOLIGANISM PERPETRATED BY SFI CRIMINALS.

their demand of a fair and transparent investigation. It is appalling that despite clear evidence of involvement of SFI in admissions through fraudulent methods, assaults on academicians and students, disruption of university activities and incidents of ragging and violence, no decisive action has been taken till date. ABVP is committed in its opposition to leftist extremism and violence and will continue to staunchly oppose it." ■

Rashtriya Chhatrashakti Team

सिद्धार्थन के दोषियों को दंडित करने की मांग को लेकर अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन



राष्ट्रीय छात्र फिल्म महोत्सव की झलकियां

